घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 27- गुरूवार 27- नवम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये ,www.ghatati-ghatana.com,RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

संविधान दिवस पर संविधान 9 नई भाषाओं में जारी

तीन तलाक खत्म करना ऐतिहासिक कदम,जीएसटी से देश की आर्थिक एकता मजबूत हुई : राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। संसद के सेंट्रल हॉल में बुधवार को 150 वां संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा- संसद ने तीन तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। राष्ट्रपति ने बताया- अनुच्छेद 370 हटाने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हुई। नारी शक्ति बंधन कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की नई शुरुआत करेगा। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारा संविधान देश के महान नेताओं ने संविधान सभा में तैयार किया था। यह दस्तावेज उन करोड़ों भारतीयों की सामूहिक बुद्धि, त्याग और सपनों का प्रतीक है, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया।

बिहार में ज्यादा वोटिंग लोकतंत्र के ताज में एक और 'कीमती हीरा' जोड़ने जैसा : उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में लोगों ने बड़ी संख्या में वोट डालकर दुनिया को फिर दिखा दिया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बिहार चुनावों में भी भारी मतदान हुआ, खासकर महिलाओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट डाले। यह भारतीय लोकतंत्र के ताज में एक और 'कीमती हीरा' जोड़ने जैसा है। उपराष्ट्रपति ने संविधान सभा की महिलाओं के योगदान की भी सराहना की और कहा कि उनका योगदान 'अतुलनीय और ऐतिहासिक' था, जिसने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत आधार दिया।

हम संविधान पर हमला नहीं होने देंगे : राहुल

संविधान को गरीब का सुरक्षा कवच बताते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लोगों से यह प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया कि 'हम संविधान पर कोई हमला नहीं होने देंगे' और कहा कि इस पर किसी भी हमले के खिलाफ खड़े होने वाले वह पहले व्यक्ति होंगे।

राष्ट्रपति बोलीं- तीन तलाक को खत्म करना ऐतिहासिक कदम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 'तीन तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करके संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी, जो आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, देश की आर्थिक एकता मजबूत करने के लिए लागू किया गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से एक ऐसी रुकावट दूर हुई, जो देश की राजनीतिक एकता में बाधा बन रही थी। नारी शक्ति बंधन कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक नया दौर शुरू करेगा। राष्ट्रपति ने बताया कि इस साल 7 नवंबर से पूरे देश में 'वंदे मातरम' की रचना के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

संविधान दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि आत्ममंथन का भी क्षण है : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि संविधान दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि आत्ममंथन का भी क्षण है। इस दिन नागरिकों को यह विचार करना चाहिए कि वे राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि हर व्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को कर्तव्य बोध कराते हुए कहा कि हमारे संविधान का आर्टिकल 51ए मौलिक कर्तव्यों को समर्पित है। ये कर्तव्य हमें सामाजिक और आर्थिक प्रगति प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। वे मानते थे कि जब हम ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो हमें अधिकार भी स्वत: मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का संविधान दिवस विशेष है क्योंकि यह सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, वंदे मातरम् के 150 वर्ष और गुरु तेग बहादुर की शहादत के 350 वर्ष का अवसर है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब भीमराव आम्बेडकर और कई प्रतिष्ठित महिला सदस्यों को याद किया, जिनकी दूरदर्शिता ने संविधान को समृद्ध बनाया।

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू दीप्ति ने आत्महत्या की

भाई का आरोप...पति और सास मारपीट करते थे

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। देश की मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया (38) ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दीप्ति का शव ड्रेसिंग रूम के पंखे से लटका हुआ मिला। दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा। हरप्रीत उन्हें लेकर अस्पताल गए, जहां दीप्ति को मृत घोषित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी हृद्ध के मुताबिक, पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में

लिखा, 'अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन होता। बेटे को मां का आशीर्वाद।' पुलिस के मुताबिक, दीप्ति और उनके पति अलग-अलग घरों में रहते थे। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने दो शादियां की हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। उसके साथ भी हरप्रीत की एक बेटी है। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने बताया कि मेरे जीजा (हरप्रीत) के कई अवैध संबंध थे। शादी के बाद से ही दोनों के अच्छे संबंध नहीं थे।

2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद हमें पता चला कि जीजा और सास मेरी बहन के साथ मारपीट करते हैं। हम अपनी बहन को कोलकाता में अपने घर ले आए थे, लेकिन उसकी सास उसे वापस ले गई थी। ऋषभ ने कहा- उसके बाद भी बहन के साथ उन्होंने मारपीट जारी रखा।

कैबिनेट मीटिंग में 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी : पुणे मेट्रो का विस्तार होगा

परमानेंट मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए 7280 करोड़ की योजना....

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 9858 करोड़ रुपए से पुणे मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। वहीं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में जरूरी होते हैं। इसके अलावा,अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने गुजरात की द्वारका-कनालूस रेलवे लाइन और महाराष्ट्र की कर्जत-बदलापुर रेलवे लाइन को डबल करने की मंजूरी दी है। यानी रेल लाइनों पर और ट्रैक बनाए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज-2 के तहत लाइन-4 (खराड़ी-हडपसर-स्वारगेट-खड़कवासला) और लाइन-4 ए (नल स्टॉप-वारजे-मानिक बाग) को मंजूरी दे दी। केंद्रीय आवास एवं

शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, दोनों कॉरिडोर कुल 31.636 किमी लंबे होंगे और इनमें 28 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। परियोजना पांच वर्ष में पूरी की जाएगी और इसकी अनुमानित लागत 9,857.85 करोड़ रुपये होगी। इसके लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाहरी वित्तीय एजेंसियां संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराएंगी। लाइन 4 और 4ए पुणे की कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का हिस्सा हैं और खराडी बाइपास, नाल स्टॉप (लाइन 2) तथा स्वारगेट (लाइन 1) पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। हडपसर रेलवे स्टेशन पर भी इंटरचेंज होगा और इसे लोनी कालभोर व ससवड रोड की ओर भविष्य के प्रस्तावित कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। यह मेट्रो लाइन आईटी पार्क, औद्योगिक क्षेत्रों, व्यापारिक जोन, शिक्षण संस्थानों और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेंगी। सोलापुर रोड, मगरपट्टा रोड, सिंहगद रोड, करवे रोड और मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्गों पर यातायात दबाव कम होगा और सुरक्षित, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बनने के बाद दैनिक यात्रियों का संयुक्त अनुमान 2028 में 4.09 लाख, 2038 में 7 लाख, 2048 में 9.63 लाख और 2058 में 11.70 लाख से अधिक होगा। लाइन 4 पर 2028 में 3.23 लाख से बढ़कर 2058 में 9.33 लाख यात्रियों द्वारा यात्रा करने का अनुमान है, जबकि लाइन 4ए पर 2028 में 85,555 से बढ़कर 2058 में 2.41 लाख यात्रियों के यात्रा करने की संभावना है। परियोजना का क्रियान्वयन महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सर्वे, डिजाइन और अन्य पूर्व निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। इस मंजूरी से पुणे मेट्रो नेटवर्क 100 किमी के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा।

लोकतंत्र और चुनावों के अंतरराष्ट्रीय संस्थान की अध्यक्षता करेंगे सीईसी ज्ञानेश कुमार

नई दिल्ली, 26 नवम्बर 2025। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (अंतरराष्ट्रीय आईडीईए) के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वे 3 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित होने वाली सदस्य देशों की परिषद की बैठक में आईआईडीईए के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अध्यक्ष के रूप में वे वर्ष 2026 के दौरान परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अंतरराष्ट्रीय आईडीईए, 1995 में स्थापित, एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विश्वभर में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और उरुग्वे सहित 35 देश हैं। अमेरिका और जापान इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। यह संगठन समावेशी, लचीली और जवाबदेह लोकतंत्रों को बढ़ावा देता है। भारत आईआईडीईए का एक संस्थापक सदस्य है, जिसने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक विमर्श और संस्थागत पहलों में निरंतर योगदान दिया है। अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेश कुमार आईआईडीईए के वैश्विक एजेंडे को आकार देने के लिए विश्व के सबसे बड़े चुनावों के संचालन के देश के अद्वितीय अनुभव का उपयोग करेंगे।

लखीमपुर खीरी : नदी में गिरी बेकाबू कार,डूबने से सिंचाई विभाग के पांच कर्मचारियों की मौत

लखीमपुर खीरी,26 नवम्बर 2025। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में एक कार बेकाबू होकर शारदा नदी में गिर गयी। पानी में डूबने से कार सवार सिंचाई विभाग के पांच कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक को गंभीर

हालत में बाहर निकाल लिया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया और स्थानीय प्रशासन को पीड़ितो की यथासंभव मदद करने के निर्देश भी दिए। पढुआ थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बुधवार को बताया कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी एक कार से लखीमपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने तैनाती स्थल गिरजापुरी बैराज जा रहे थे।

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली

2030 में अहमदाबाद में होंगे गेम्स,ओलिंपिक 2036 की दावेदारी मजबूत होगी

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया। भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते थे।

20 साल बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा : 20 साल के बाद भारत में कोई

मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के अलावा, भारत 1951 और 1982 एशियन गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है। 2003 में हैदराबाद में एफ्रो-एशियन कप का आयोजन भी हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसी भी देश के लिए सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि, विकास क्षमता, इन्फ्रास्ट्रक्चर और विजन का भी प्रतीक माना जाता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित कुल 9 देश इसकी मेजबानी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 5 बार मेजबानी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है।

ओलिंपिक-2036 की दावेदारी मजबूत होगी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से ओलिंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होगी। भारत 2036 के ओलिंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। क्करूनरेंद्र मोदी ने लाल किले की से इसका ऐलान किया था। पिछले साल नवंबर में भारत ने ओलिंपिक गेम्स-2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की थी।

लालकिला धमाका मामले में आतंकी उमर नबी का साथी शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार

फरीदाबाद,26 नवम्बर 2025। दिल्ली के लालकिला बम धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुसाइड हमलावर आतंकी डॉ. उमर नबी के नजदीकी सहयोगी शोएब को फरीदाबाद के गांव धौज से गिरफ्तार कर लिया है। शोएब हरियाणा के अल-फलाह विश्वविद्यालय में वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत था। आरोप है कि उसने उमर नबी को विस्फोटक सामग्री लाने और ले जाने में सहायता की और नूंह में अपनी साली अफसाना के घर में उसके लिए कमरा किराए पर दिलवाया। धमाके से पहले उमर नबी 10 दिन तक वहीं ठहरा था। इस मामले में यह 7वीं गिरफ्तारी है।

आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉ. मुजम्मिल शकील की निशानदेही के बाद अब एनआईए डॉ. आदिल अहमद और डॉ. शाहीन सईद को अल-फलाह विश्वविद्यालय में लेकर जाएगी। जांच में सामने आया है कि आदिल और उमर नबी कई वर्षों से परिचित थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने यूपीएससी को योग्यता और सत्यनिष्ठा पर आधारित राष्ट्र निर्माण का एक स्तंभ बताया

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। नई दिल्ली में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने आयोग की 100 वर्षों की यात्रा की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतांत्रिक और प्रशासनिक विकास में एक युग-परिभाषित अध्याय बताया। अपने संबोधन में बिरला ने कहा कि योग्यता, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों में निहित इस संस्था ने लाखों युवा

भारतीयों को सार्वजनिक सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जैसे-जैसे भारत साल 2047 तक एक विकसित और समावेशी राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, यूपीएससी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच, यूपीएससी ने अपनी चयन प्रक्रियाओं को अधिक उन्नत, वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाकर सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए हैं।

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एसएईएसआई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएमआर एयरोस्पेस और औद्योगिक पार्क- एसईजेड, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद स्थित सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया (एसएईएसआई) सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि आज से भारत का एविएशन नई उड़ान भर रहा है। उन्होंने बताया कि सफ़रान की नई सुविधा भारत को

ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। यह सुविधा न केवल तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सफ़रान का भारत में निवेश आगे भी इसी गति से जारी रहेगा। वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं अब आसमान की ऊंचाइयों को छू रही हैं और देश का विमानन क्षेत्र उनकी महत्वाकांक्षाओं को नई ऊर्जा दे रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि एमआरओ क्षमताएं देश में ही मजबूत हों, जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो सके। अपने संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। बढ़ती मांग के कारण मेंटेनेंस, रिपेयर और एमआरओ सेवाओं की आवश्यकता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत का लगभग 85 प्रतिशत एमआरओ कार्य विदेशों में होता था, जिससे लागत बढ़ती थी और विमानों को लंबे समय तक जमीन पर खड़ा रहना पड़ता था।

संपादकीय

चाहे संसद का कोई भी सदन हो... आलोचना के लिए भी जगह होनी चाहिए

संसद का शीत सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यसभा बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें सदस्यों के लिए करने और न करने वाली बातों का जिक्र है। इसी बुलेटिन के मुताबिक,सभापति के निर्णय की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

बुलेटिन में कहा गया है कि सभापति सदन के पूर्व उदाहरणों के अनुसार निर्णय देते हैं और जहां कोई पूर्व उदाहरण नहीं होता, वहां सामान्य संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है। जाहिर तौर पर इस दिशानिर्देश का मकसद राज्यसभा की कार्यवाही को बेहतर बनाना है, लेकिन इसमें आलोचना की भी जगह होनी चाहिए।

आलोचना और वाद-विवाद संसदीय परंपरा का हिस्सा हैं। जब तक कि आलोचना पूर्वाग्रह से ग्रसित या व्यक्तिगत न हो, तब तक उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यही भाव देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी है, मसलन- अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। फैसलों से असहमति जताई जा सकती है और उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। आलोचना और असहमति की आजादी के बिना यह संभव न होता।

चुनावी राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष से हर बात पर सहमति की उम्मीद करना बेमानी है। फिर अभी देश का जैसा सियासी माहौल है, उसमें सदन के भीतर और बाहर टकराव आम है। पिछले कई उदाहरण हैं,जहां विपक्ष और चेयर के बीच तनाव भरे रिश्ते देखने को मिले। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदड़ धनखड़ के कार्यकाल में तो यह तनाव बिल्कुल चरम पर था। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की एक टिप्पणी को लेकर राज्यसभा की प्रिविलेज कमिटी में मामला चल रहा है, जो उसी तनाव का नतीजा है।

लोकतंत्र में कोई भी आलोचना के परे नहीं कहा जा सकता। यह तो बेहतरी का जरिया है। राज्यसभा बुलेटिन से ऐसा भी लग सकता है कि सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। हां, इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति या आलोचना का अधिकार भी कुछ सीमाओं के साथ लागू होता है।

शीत सत्र वैसे भी सरकार और विपक्ष के संबंधों की नई आजमाइश है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए यह पहला सेशन है। मॉनसून सत्र का अनुभव अच्छा नहीं था। तब राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी केवल 38.88 प्रतिशत थी और केवल 41.15 घंटे काम हो पाया था। इस बार भी एसआईआर का मुद्दा गरम है। राधाकृष्णन के सामने संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

आईएएस अधिकारी के बच्चे आईएएस नहीं बनना चाहते?

जब प्रशासन बदलता है दिशा–क्यों भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे उसी राह पर कम चलते हैं?

प्रतिष्ठा की चमक के पीछे छिपी कठोर सच्चाइयों और नई पीढ़ी की बदलती आकांक्षाओं का विस्तृत विश्लेषण

प्रियंका सौरभ
आर्यनगर,
हिसार
(हरियाणा)

भारतीय प्रशासनिक सेवा को समाज में सम्मान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है,परंतु इसके भीतर छिपी कठोर वास्तविकताएँ अक्सर परिवारों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। तेज़ स्थानांतरण, राजनीतिक दबाव, सीमित निजी समय और निरंतर सार्वजनिक अपेक्षाएँ नई पीढ़ी को इस सेवा से दूर करती हैं। साथ ही, बच्चों को उपलब्ध व्यापक शिक्षा और वैश्विक अवसर उन्हें विविध करियर चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे उसी राह पर कम चलते हैं और जीवन-संतुलन तथा रचनात्मक स्वतंत्रता आधारित नए करियर को प्राथमिकता देते हैं।

भारत में प्रशासनिक सेवा को लंबे समय से शक्ति, प्रतिष्ठा और राष्ट्र-निर्माण के सर्वोच्च प्रतीकों में गिना जाता रहा है। समाज में आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा एक ऐसा नाम है जो सम्मान, अधिकार और सफलता की सम्मिलित छवि बनाता है। किंतु विडंबना यह है कि जिन परिवारों ने इस प्रतिष्ठा को बहुत निकट से देखा है, वही परिवार–विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे–बहुत कम संख्या में उसी पेशे की राह अपनाते हैं। यह प्रश्न केवल सामाजिक जिज्ञासा भर नहीं है; यह प्रशासनिक जीवन की कठोर सच्चाइयों, बदलते समय और नई पीढ़ी की मनोवृत्ति का गहरा संकेत है।

सबसे पहले,भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चे उस सेवा की वास्तविक कठिनता को प्रतिदिन देखते हैं जिसे बाहरी दुनिया केवल प्रतिष्ठा के आवरण में देखती है। अनिश्चित और तेज़ स्थानांतरण,राजनीतिक दबाव, जनता की अपेक्षाओं का अंतहीन बोझ, अवकाश का अभाव और निरंतर संघर्ष–इन सभी का प्रभाव परिवार के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। नई पीढ़ी जिसके लिए मानसिक स्वतंत्रता और कार्यजीवन संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है,वह ऐसी सेवा की ओर आकृष्ट नहीं होती जहाँ व्यक्तिगत समय और निजी जीवन लगभग समाप्त हो जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है–आर्थिक सुरक्षा। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा, उत्कृष्ट वातावरण और व्यापक अवसर प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए सरकारी सेवा प्राप्त करने का संघर्ष किसी अनिवार्यता के स्थान पर एक अतिरिक्त बोझ जैसा प्रतीत होने लगता है। संघ लोक सेवा आयोग की कठिन, अनिश्चित और समयसाध्य परीक्षा उनके लिए आवश्यक विकल्प नहीं, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण यात्रा जैसी लगती है। इसलिए उनकी राहें निजी क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान, विधि-विज्ञान या उद्यमिता की ओर अधिक मुड़ जाती हैं–जहाँ आय अधिक है, स्वतंत्रता अधिक है और स्थानांतरण या राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियाँ कम हैं।

तीसरी सच्चाई यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के भीतर की जो प्रशासनिक सीमाएँ हैं–फाइलों का व्यवहार, विवश निर्णय,भ्रष्ट तंत्र का दबाव–वे सब इन परिवारों के बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके माता-पिता कई बार अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय नहीं ले पाते,तो यह उनके भीतर प्रशासनिक सेवा की शक्ति को कम प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है। समाज इसे चाहे जितना सम्मानजनक माने, परिवार के भीतर इसका वास्तविक चित्र कई बार निराशाजनक होता है।

चौथा पहलू है–नई पीढ़ी की मूल्य-दृष्टि। आज की युवा पीढ़ी सरकारी पदों की स्थिरता से अधिक वैश्विक अवसरों, रचनात्मक स्वतंत्रता, डिजिटल माध्यमों पर आधारित करियर और नव-उद्यम संस्कृति की ओर आकर्षित है। वे जोखिम उठाने को तैयार हैं, परंतु बंधी-बंधाई व्यवस्था में रहना नहीं चाहते। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी सेवा जहाँ नियम कठोर हैं, प्रक्रिया विस्तृत है और ऊर्जा का बड़ा भाग व्यवस्था को संचालित रखने में व्यतीत होता है–वहाँ उन्हें अपनी क्षमता का पूर्ण विस्तार नहीं दिखाई देता।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अपने बच्चों को इस सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। वर्षों की थकान, संघर्ष और भारी दबाव के बाद वे अपने बच्चों के लिए अधिक संतुलित,स्वतंत्र और अपेक्षाकृत शांत जीवन की कल्पना करते हैं। यह माता-पिता की सहज मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, और बच्चों के करियर चयन को गहराई से प्रभावित करती है।

यह पूरा परिदृश्य एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। वह समय अब समाप्त हो रहा है जब भारतीय प्रशासनिक सेवा को करियर का सबसे उत्कृष्ट विकल्प माना जाता था। आज अनेक प्रतिष्ठित और प्रभावी करियर उपलब्ध हैं जिनमें स्वतंत्रता, रचनात्मकता,सम्मान और आय–सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। इस परिवर्तित परिदृश्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आकर्षण को कुछ हद तक कम किया है, विशेष रूप से उन परिवारों में जिन्होंने इसकी चमक के पीछे की कठोर थकान को निकट से महसूस किया है।

फिर भी यह सत्य है कि यह रुझान प्रशासनिक सेवा की महत्ता को कभी समाप्त नहीं करता। भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की प्रशासनिक रीढ़ है और इसमें आने वाले युवा राष्ट्र को दिशा देने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब इस सेवा की राह वही चुनता है जो इसे मन से अपनाना चाहता है–न कि वह जो सामाजिक दबाव या मजबूरी में प्रवेश करता है।

अंततः, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बच्चों का उसी सेवा में न जाना किसी प्रकार की असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि बदलते भारत की सूक्ष्म मानसिकता का परिचायक है–एक ऐसा भारत जहाँ विकल्प अधिक हैं, अपेक्षाएँ नवीन हैं, और करियर का अर्थ केवल प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी है। यह परिवर्तन सकारात्मक है,क्योंकि यह दिखाता है कि नई पीढ़ी उस संसार का स्वप्न देखती है जहाँ पेशा शक्ति से नहीं, बल्कि संतुलन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संतोष से निर्धारित होता है।

नारी शिक्षा और साक्षरता से प्रस्फुटित भविष्य के नए आयाम

स्त्रियों को मुक्त आकाश की दरकार

संजीव ठाकुर,
रायपुर छत्तीसगढ़

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या में स्त्रियों और बच्चों की संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की, किंतु सामाजिक ढांचे में स्त्री-शोषण, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, असमानताओं और अवसरों की कमी ने आज भी महिलाओं को उनके मूल अधिकारों विशेषतः शिक्षा और सुरक्षा से वंचित कर रखा है, यही कारण है कि आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा और साक्षरता को केवल सामाजिक आवश्यकता न मानकर सामाजिक क्रांति का आधार माना जाने लगा है, क्योंकि स्त्री केवल परिवार की संरक्षिका नहीं बल्कि भविष्य की जननी, समाज की प्रथम मार्गदर्शक और संस्कारों की आधारशिला है, और जब स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने परिवार और बच्चों को अच्छे-बुरे,सुरक्षित-असुरक्षित, सामाजिक-असामाजिक के अंतर को समझाती है, यही चेतना आगे चलकर एक सामाजिक परिवर्तन और व्यापक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती है,आज भारत में कोरोना संक्रमण से लेकर स्वास्थ्य, आर्थिक विवेक, स्वच्छता, तकनीकी विकास, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों तक हर मुद्दे पर शिक्षा और साक्षरता की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिस प्रकार जल के बिना जीवन असंभव है उसी प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा और निरर्थक है,किंतु यहाँ आवश्यक है कि शिक्षा और साक्षरता के अंतर को समझा जाए, क्योंकि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने,रोजगार पाने या तकनीकी

दक्षताओं तक सीमित है जबकि शिक्षा व्यक्ति का समग्र विकास करती है जिसमें बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिपक्वता शामिल है, शिक्षा व्यक्ति को सभ्य और विवेकी बनाती है,उसके भीतर संतुलन, सद्बुद्धि और मानवीय संवेदनाएँ विकसित करती है, जबकि साक्षरता केवल वेतन,पद, और व्यावसायिक लाभ से जुड़कर रह जाती है, यही कारण है कि आज उच्च शिक्षित लेकिन व्यवहारिक रूप से अज्ञानी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो समाज के लिए चुनौती बनते दिखाई देते हैं,इतिहास में रावण प्रकांड विद्वान था पर स्त्री-अपहरण जैसी कृत्य ने उसकी विद्वता को व्यर्थ कर दिया,आधुनिक समाज में केतन पारेख और हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज तथा ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी साक्षर तो थे पर शिक्षित नहीं थे,इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का संबंध चरित्र-निर्माण से है मात्र रोजगार से नहीं, शिक्षा घर से शुरू होती है जहाँ मां प्रथम गुरु होती है और गर्भकाल से ही संस्कारों का प्रभाव पड़ता है,अभिमन्यु इसका सर्वोत्तम उदाहरण है,महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन दोनों ने स्वीकार किया कि बच्चे के चरित्र-निर्माण में माताओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके बाद विद्यालय, शिक्षक और खेल-कूद जीवन में अनुशासन, नेतृत्व, सहभागीभाव और ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करते हैं, इसीलिए कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान नहीं,

वहीं सुकरात का यह कथन–मैं इसलिए ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता।

शिक्षा की विनम्रता और मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देता है, परंतु आज प्रतिस्पर्धा के युग में समाज ने साक्षरता को शिक्षा का स्थान दे दिया है, नौकरी,वेतन, पद और आर्थिक चमक के कारण नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत और चरित्र निर्माण पीछे छूट गए हैं, इसी वजह से शिक्षा में नकल, फर्जीवाड़ा, धन देकर नौकरी पाना और भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं जिससे सामाजिक मूल्य संकट में पड़ने लगे हैं, ऐसे समय में आवश्यकता है नैतिक साक्षरता की–ऐसी शिक्षा की जो ज्ञान के साथ-साथ संवेदना, जिम्मेदारी और सांस्कृतिक चेतना को विकसित करे, विशेष रूप से महिलाओं में यह शिक्षा एक सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है, क्योंकि शिक्षित स्त्री शोषण से लड़ना जानती है, अपने अधिकार पहचानती है, परिवार को सही दिशा देती है और आने वाली पीढ़ियों को सुसंस्कृत बनाती है, वास्तव में स्त्री का शिक्षित होना सिर्फ उसके परिवार का उत्थान नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति की कुंजी है, इसलिए आज भारत को केवल साक्षर नागरिक नहीं बल्कि शिक्षित, संवेदनशील,मूल्य-सम्पन्न और संस्कारित नागरिकों की आवश्यकता है, विशेषतः शिक्षित स्त्रियाँ ही समाज में वास्तविक जागरूकता, समानता और नैतिकता की नींव मजबूत कर सकती हैं, क्योंकि साक्षरता हमें पेशा दे सकती है पर शिक्षा हमें इंसान बनाती है, और जब समाज मनुष्यता, संवेदना, समानता और न्याय की राह पर चलेगा तभी भारत एक सशक्त, सुरक्षित और संस्कारित राष्ट्र बन सकेगा, इसलिए स्त्री पढ़ेगी तो इतिहास रचेगी और नारी जागेगी तो समाज आगे बढ़ेगा।

अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस

मध्यप्रदेश में मोहन यादव का सख्त संकेत

-पवन वर्मा-विभूति फीचर्स-

मध्यप्रदेश की कानून-व्यवस्था पर पिछले कुछ दिनों से उठ रहे सवालों ने अंततः सत्ता के शीर्ष को हिला दिया है। मंगलवार रात को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अचानक पुलिस मुख्यालय पहुँचना, और वहाँ दिए गए तीखे तेवरों वाले निर्देश,यह साफ कर गए कि सरकार अब चेतावनी की मुद्रा में नहीं, बल्कि कार्रवाई के मोड में है। मध्यप्रदेश के रायसेन व भोपाल में हुई हालिया आपराधिक घटनाएँ भले अलग-अलग प्रकृति की हों, पर एक बात दोनों में समान थी, राज्य की पुलिस व्यवस्थाओं पर सीधे सवाल। रायसेन में जो कुछ हुआ, वह केवल किसी स्थानीय तंत्र की चूक नहीं थी, बल्कि कानून-व्यवस्था पर एक गंभीर धब्बा था। सबसे वीभत्स घटना गौहरगंज की रही,जहाँ छह साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म ने न केवल ज़िले, बल्कि पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। यह वह बिंदु था, जहाँ मुख्यमंत्री का धैर्य टूटा और उनका रुख स्पष्टतः कड़ा हो गया।

मुख्यमंत्री की नाराज़गी सिर्फ शब्दों तक नहीं रही। रायसेन एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन्होंने पुलिस महकमे को एक ठोस और निर्विवाद संदेश दिया कि सुरक्षा में असफलता की कोई गुंजाइश नहीं, और ऐसी असफलता का मूल्य पद से चुकाना होगा। यह निर्णय केवल एक अधिकारी का तबादला भर नहीं है, यह उन सभी जिलों के लिए संकेत है जहाँ अपराधियों का मनोबल पुलिस की सुस्ती से बढ़ने लगा है।

गौहरगंज कांड पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया में वह बेचैनी साफ झलकती है, जो किसी भी जागरूक शासन प्रमुख में होनी चाहिए। छह साल की बच्ची के साथ हुई यह अमानवीय वारदात केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि राज्य की सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की परीक्षा भी है। मुख्यमंत्री ने इसे पुलिस की ÷निगरानी की विफलता÷ करार दिया, जो मुख्यमंत्री की एक सही और आवश्यक टिप्पणी थी। क्योंकि यह प्रश्न लंबे समय से अनुत्तरित है कि छोटे जिलों में इस प्रकार की घटनाएँ अचानक कैसे बढ़ रहीं हैं, और अपराधी अवसर कैसे पा रहे हैं?

राजधानी भोपाल की घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई। राजधानी में बढ़ती लापरवाही का अर्थ पूरे प्रदेश के लिए खतरे का संकेत है। राजधानी वह आइना है जिसमें सरकार की प्राथमिकताएँ और पुलिस की सतर्कता स्पष्ट दिखती है। यह बात मुख्यमंत्री ने मीटिंग में साफ कर दी है कि ÷राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अनुकरणीय होनी चाहिए, असुरक्षा का प्रतीक नहीं।÷

मुख्यमंत्री के तेवरों का सार एक ही था, कि अपराध रोकना अब पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, केवल अपराधियों को पकड़ लेना ही उसका 'काम' नहीं है। यह सोच वर्षों से चली आ रही उस कार्यशैली को भी चुनौती देती है जिसमें पुलिस प्रायः 'घटना के बाद की कार्रवाई' पर जोर देती रही है, रोकथाम पर नहीं। मुख्यमंत्री का यह दृष्टिकोण स्वागत योग्य है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल तब तक नहीं टूटता, जब तक उन्हें यह भरोसा रहता है कि पुलिस की चौकसी में कहीं न कहीं ढील है।

रायसेन एसपी का हटाया जाना आने वाले समय के लिए एक निर्णायक मोड़ होगा। यह पुलिस कप्तानों और जिलों के अधिकारियों को यह समझा रहा है कि अब आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं, जमीन पर ठोस नतीजे मायने रखेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और संगठित अपराधों पर नियंत्रण,इन मोर्चों पर सरकार अब प्रत्यक्ष निगरानी करेगी और लापरवाही की कीमत तुरंत चुकानी पड़ेगी।

इस पूरी घटना का बड़ा संदेश यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अब कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर राजनीतिक जोखिम लेने को भी तैयार हैं। प्रशासनिक फेरबदल हो या सख्त निर्णय,वे यह दिखा रहे हैं कि ÷अपराध के प्रति शून्य-सहनशीलता÷ केवल नारा नहीं, बल्कि क्रियान्वयन का सिद्धांत होगा।

प्रदेश की जनता यही चाहती है कि शासन की संवेदनशीलता सिर्फ बयान या दौरे तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर महसूस हो। जिस तरह रायसेन की मासूम बच्ची की वेदना ने सबको झकझोरा, उसी तरह मुख्यमंत्री की कार्रवाई ने पुलिस तंत्र को जगाया है। यह जागरण तभी सार्थक होगा जब हर जिले में अपराधियों के मन में यह भय जन्म ले कि इस सरकार में गलती की नहीं, 'अपराध की सोच' की भी सजा है।

मध्यप्रदेश आज कानून-व्यवस्था के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मुख्यमंत्री का यह लौह-मुष्टि वाला रुख उम्मीद जगाता है कि आने वाला समय अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित होगा।

देश में एक नया खेल शुरू...

सुभाष बुड़ावन
वाला,रतलाम.मप्र.

देश में एक नया खेल शुरू हो चुका है! अपराध नहीं होता, पहले उसकी पहचान होती है, धमाका नहीं गूँजता, पहले धर्म गूँजता है, लाल किले के पास धमाका हुआ पर देश हिला नहीं, देश बस उत्सुक हुआ कि देखें, इस बार किसका नंबर निकला। वीडियो आया,खून बिखरा, लोग मरे, पर जनता अपने सोफे पर बैठी स्क्रीनशॉट ज़ूम कर रही थी कि हमलावर की दाढ़ी कितनी लंबी, टोपी किस रंग की, आवाज़ कैसी, क्योंकि नीयत, सोच, आतंकवाद,ये सब बाद में देखे जाते हैं, पहले पहचान की अदालत लगती है।

राजनीति इस तमाशे पर खिल उठती है, नेता एक के बाद एक दोगली हँसी के साथ बयान छोड़ते हैं,एक वह भटका हुआ था, दूसरा बोलता है वह हमारे समुदाय का हो ही नहीं सकता, तीसरा कहता है वीडियो फेक है, चौथा कहता है धर्म मत देखिए और अगले ही पल पीड़ितों की जाति गिनकर राजनीति का नया शोर मचा देता है, सच तो इन बयानबाजियों के बीच इतना पिसता है कि लगता है वह आलोचनाओं से बचने के लिए किसी दूसरे देश में शरण माँग लेगा। सदियों से आतंकी संगठन युवाओं को बहकाने के लिए धर्म का मुखौटा लगाकर हिंसा बेचते हैं, पर हमारे समाज ने उन्हें पछाड़ दिया,हम खुद हर अपराध को धर्म और जाति के आइटम नंबर में बदल देते हैं, और आतंकवादी सोचते होंगे कि काम तो हमने आधा किया था, समाज ने पूरा कर दिया! त्योहार अब भक्ति के नहीं, पहचान की जाँच के दिन बन चुके हैं, नवरात्रि में कौन आया, किस रंग का कपड़ा पहना, किस गाने पर नाचा, सबकी स्कैनिंग हो रही है, भगवान से ज़्यादा व्यस्त पुलिस और मीडिया हैं, जातिवाद तो इस देश का पुराना महावीर है, जो हजारों लोगों को बिना आवाज़ और बिना विस्फोट के खत्म करता है, पर उसे परंपरा का हिस्सा मानकर सम्मान दिया जाता है, आतंकवादी तो खैर एक बार मारता है, जातिवाद हर दिन मारता है, धीरे-धीरे,नियमित किस्तों में।

किसी भी हमले के बाद लोग तथ्य नहीं, पहचान ढूँढते है,कौन थे वो? अपराध की गंभीरता बाद में देखी जाती है, पहले धर्म की एक्सेल शीट अपडेट की जाती है, सोशल मीडिया योद्धा नए निष्कर्ष सुनाते हैं,30 सेकंड का वीडियो देखकर 300 साल का इतिहास समझा देते हैं, और यदि सरकार या एजेंसी उनकी पसन्द का बयान न दे, तो कहते हैं कि एजेंसियाँ बिक गई हैं, यह ज्ञान नहीं, अज्ञान का चरम रूप है; राजनीति अंदर ही अंदर हर धमाके पर खुश होती है, क्योंकि धमाका मतलब डिबेट, डिबेट मतलब टीआरपी, टीआरपी मतलब वोट, वोट मतलब सत्ता,और सत्ता ही तो वह देवता है जिसके नाम पर नफरत के सारे अनुष्ठान चल रहे हैं।

असली सवाल कि आतंकी क्यों बनता है,किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली चर्चा दो लाइन में समा जाती है,÷हमारे लोग निर्दोष, उनके लोग दोषी,÷ आतंकवादी को खत्म करना आसान है,गोलियाँ चलेंगी, ठिकाने मिटेंगे, पर उस मानसिकता को कौन खत्म करेगा जो हर अपराध में धर्म खोजती है, हर विवाद में जातियाँ गिनती है, और हर घटना को पहचान की आरी से काटकर परोसती है? यही वह विचार है जो असली आतंकवाद से भी खतरनाक है, क्योंकि आतंकवादी कभी-कभी हमला करता है, हमारी नफ़रत हर दिन हमला करती है, आतंकवादी एक शहर हिलाता है, हमारी सामूहिक मानसिकता पूरा देश हिला सकती है, और वह दिन दूर नहीं जब किसी विस्फोट से ज्यादा डर समाज की प्रतिक्रिया से लगेगा, न्याय नहीं, नैरेटिव तय करेगा कि अपराधी कौन है, पीड़ित कौन है, और देशद्रोही कौन है, और वही दिन होगा जब इस देश का सबसे खतरनाक आतंकवादी कोई संगठन नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच बन जाएगी!

ममता एसआईआर के विरोध के नाम पर दे रही हैं घुसपैठियों का साथ

अजय कुमार,
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवि न) प्रक्रिया का जबर्दस्त विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह प्रक्रिया भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ममता का यह भी आरोप है कि एसआईआर के तहत घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने का नाम लेकर असली वोटरों को भी परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इस विरोध के पीछे दो पहलू हैं÷ एक तो ममता का अल्पसंख्यक वोट बैंक बचाने का प्रयास, और दूसरा पश्चिम बंगाल में चुनावी फायदे की नजर से यह विरोध। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू न करने की निंदा की है। ममता ने चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखकर इस

प्रक्रिया को अव्यवस्थित, खतरनाक और बिना तैयारी के बताया है और इसे रोकने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को इस प्रक्रिया में काम करने में जो परेशानी हो रही है, वह तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार के एसआईआर विरोध के चलते है। बीएलओ यूनाइटेड फोरम के अनुसार, प्रदेश में बीएलओ को राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी तत्व धमका रहे हैं, जिससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। बीएलओ के लिए उचित सुरक्षा, ट्रेनिंग और प्रशासनिक सहूलियत नहीं मिल रही है; वे अपने स्कूलों में भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं और उनके ड्यूटी आवंटन में अनियमितता है। इसके अलावा, उन्हें काम का अत्यधिक दबाव, डेटा में त्रुटियां, सर्वर फेलियर जैसी तकनीकी समस्याएं झेलनी पे रही हैं और बिना कारण बताए डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकियां मिल रही हैं। ममता सरकार की यह रणनीति बीएलओज को भयभीत करके एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने की है, ताकि फर्जी वोटर सूची में बने रह सकें और घुसपैठियों या फर्जी वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया सफल न हो। इस कारण प्रभावी तरीके से केवल पश्चिम बंगाल में ही बीएलओ को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगने वाले दबाव और समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि बीएलओ अपने हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के रूप में पुलिस कार्रवाई व अन्य समर्थन नहीं मिल रहा, जिससे बीएलओ और ज्यादा दबाव में हैं। इस प्रकार, ममता सरकार का एसआईआर विरोध और बीएलओ पर हो रहे दबाव की जे में सीधा राजनीतिक हित है। ममता बनर्जी अल्पसंख्यक वोटरों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को बचाने के लिए इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बीएलओ, जो घर-घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं, उन्हें दंडित करने, धमकाने एवं उनकी सहायता रोकने की क्रियाएं इस विरोध का हिस्सा हैं। पश्चिम बंगाल में यह स्थिति इसलिए विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि यहां के वोट बैंक में अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा है और ममता सरकार उसे खोना नहीं चाहती। कुल मिलाकर, ममता बनर्जी का एसआईआर विरोध घुसपैठियों के वोट को लेकर उनकी चिंता के साथ-साथ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जबकि बीएलओ को इस प्रक्रिया में कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव की वजह से काम करना कठिन हो रहा है ।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

CMYK

सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषय पर एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन

होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज,अंबिकापुर में जनजातीय समाज का गौरव शाली अतीतः ऐतिहासिक...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

स्थानीय होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर में दिनांक 25 नवंबर को 'जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत : ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान' विषय पर एक दिवसीय कला-संस्कृति केंद्रित प्रदर्शनी का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉ. (सि.) मंजू टोप्पो ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' एवं राजकीय गीत 'अरपा पैरी के धार' के सामूहिक गायन के साथ हुआ। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन एवं महान आदिवासी विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात प्रार्थना गीत की मधुर प्रस्तुति ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उप प्राचार्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदर्शनी की विषय-वस्तु पर प्रकाश डाला तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन की महत्ता पर बल दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत करमा नृत्य ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके उपरांत अतिथियों को स्मृति-चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री इंदर भगत (प्रदेश प्रवक्ता, जनजाति गौरव समाज, छत्तीसगढ़ एवं सह संयोजक, जनजाति सुरक्षा मंच) ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों की कला एवं संस्कृति पर आधारित जीवंत प्रदर्शनी की अतिथियों ने सराहना की। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने सरगुजा की आदिवासी विभूतियों को स्मरण करते हुए कहा– 'आदिवासी संस्कृति देश की सर्वोत्तम संस्कृतियों में से एक है, जो प्रकृति के संरक्षण का अनूठा संदेश देती है। हमें इसे सहेजना और आगे बढ़ाना होगा।' कार्यक्रम का सफल संयोजन अलमा मिंज (सहायक प्राध्यापक ,समाज कार्य) द्वारा तथा सह-संयोजन रागिनी ब्रिजिट लकड़ा (सहायक प्राध्यापक , वाणिज्य) द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन श्री साबिर अली सहायक (प्राध्यापक वाणिज्य) ने किया कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकों तथा छात्राओं की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही।

होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज में संविधान दिवस पर दिलाई गई शपथ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज में संविधान निर्माण व उसकी उपादेयता विषय पर राजनीति शास्त्र की सा प्रा. राजनीति शास्त्र प्रतिभा मिंज ने बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी व्याख्यान दिया। इसके साथ ही डॉ. तृप्ति पांडेय (डीन) समाज विज्ञान संकाय द्वारा संविधान का पालन करने और उसके प्रति जागरूक रहने की शपथ छात्राओं व स्टाफ को दिलाई गई। कार्यक्रम का संयोजन प्रतिभा मिंज साप्रा राजनीति शास्त्र और पुष्पा चौबे साप्रा अंग्रेजी द्वारा किया गया। कार्यक्रम समाज विज्ञान संकाय गतिविधि डीन डॉ कल्पना गुप्ता, साप्रा अर्थशास्त्र डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. सीमा मिश्रा विभागाध्यक्ष भूगोल, अलमा मिंज विभागाध्यक्ष सोशल वर्क, सोनी वर्मा साप्रा अर्थशास्त्र व प्रेरणा लकड़ा साप्रा सोशल वर्क सहित अनेक प्राध्यापकगण की उपस्थिति व प्राचार्य डॉ. सिस्टर शांता जोसेफ के मार्गदर्शन तथा उपप्राचार्य डॉ. सिस्टर मंजू टोप्पो के निर्देशन में संपन्न हुआ।

मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस का भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण : भारत सिंह सिसोदिया

पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के बयान पर प्रतिक्रिया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और तथ्यहीन है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव द्वारा यह आरोप लगाना कि कथित 'चिन्हांकित' या 'विशेष' लोगों के नाम जानबूझकर मतदाता सूची में नहीं जोड़े जा रहे– न सिर्फ निराधार है, बल्कि निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करने वाला राजनीतिक प्रयास भी है। उक्त बातें कहते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित होती है। इसमें –सबसे पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होती है।

इसके बाद 30 दिनों तक प्रत्येक पात्र नागरिक को फार्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने, फार्म-7 से आपत्ति लगाने और फार्म-8 से विवरण संशोधन करने का अधिकार दिया जाता है। BLO के सत्यापन तथा ERO द्वारा दस्तावेज़ आधारित निर्णय के बाद ही नाम जोड़ा या संशोधित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी

राजनीतिक दल या नेता के हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा बिना किसी तथ्य,वार्ड,अधिकारी या दस्तावेज़ का उल्लेख किए आरोप लगाना– चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की निष्ठा पर संदेह उत्पन्न करता है,जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत सिंह सिसोदिया ने टी एस सिंहदेव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया से क्यों डर रही है?' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में ऐसे लोगों तक को मतदाता सूची में शामिल कराया गया,जिनका 2003 के रिकॉर्ड में कहीं उल्लेख नहीं है। अब जब व्यवस्थित सत्यापन हो रहा है, तो कांग्रेस को भय है कि उसके द्वारा प्रायोजित फ़र्जी वोटर्स सामने आ जाएंगे। इसी वजह से भ्रम फैलाने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का जनाधार खिसक चुका है,पार्टी कमजोर हो चुकी है वहीं भाजपा के कार्यकर्ता एसआईआर के इस महाभियान को सफल बनाने में समर्पित भाव से जुटे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में आ गया है और इनके नेता हताश हो कर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ।

श्री सिसोदिया ने सभी मतदाताओं से अपील की और कहा कि कांग्रेस के भ्रामक बयानों से दूर रहें, अपने आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें,बीएलओ के सत्यापन में सहयोग करें,और यदि ड्राफ्ट सूची में नाम न मिले तो निर्धारित समयावधि में फॉर्म-6 भरकर अपना नाम अवश्य जोड़ें। भाजपा का स्पष्ट मत है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए,परंतु समाज को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की प्रवृत्ति को जनता भलीभांति समझती है। निर्वाचन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन पूरी तरह पारदर्शी है, और इस पर अनावश्यक अविश्वास उत्पन्न करना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा प्रहार है, जिसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है।

भारत के राष्ट्रपति के समक्ष केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और एसकेएम का संयुक्त प्रतिनिधित्व

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपनी समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान की माँग को लेकर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 26 नवंबर 2024 को भी ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था और ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। हम एक बार फिर यह ज्ञापन आपके समक्ष इस आशा के साथ भेज रहे हैं कि आप देश की इन दो प्रमुख उत्पादक शक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे। हमने 26 नवंबर को लामबंदी के माध्यम से विरोध दिवस के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि इसी दिन ट्रेड यूनियनों ने मज़दूर-विरोधी चार श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। सरकार ने हमारी मांगों पर विचार करने के बजाय, भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए बिना ही 21 नवंबर 2025 को अचानक 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया है। इसी प्रकार, हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यूके

सीईटीए भी भारत की खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सीधा हमला है। यह समझौता ब्रिटिश कृषि व्यवसायों को भारतीय बाजारों में सस्ते डेयरी, गेहूं और मांस की बाढ़ लाने की अनुमति देगा - जो भारत-आसियान एफटीए से हुई तबाही का प्रतिबिंब है, जिसने केरल में रबर की कीमतों में 70% की गिरावट की थी। यह सौदा भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को ब्रिटिश कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए भी खोलता है, जिससे अस्पतालों के निजीकरण में तेजी आएगी और दवा एकाधिकार का विस्तार होगा जो दवाओं को बढ़ावा देगा। ट्रम्प प्रशासन द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध में, कई अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र, मत्स्य पालन और पशुपालन आदि गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

मुख्य मांगें हैं: सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद के साथ सी2+50% पर एमएसपी, चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें, किसी भी रूप में श्रम का ठेकाकरण या आउटसोर्सिंग न करें। श्रम नीति-श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा वापस लें। संगठित, असंगठित, स्कीम श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों और कृषि क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिए 26000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और 10000 रुपये प्रति माह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करें। रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण न किया जाए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को रद्द किया जाए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएँगे, कृषि पंपों के लिए मुफ़्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ़्त बिजली; विद्युत संशोधन विधेयक 2025 वापस लिया जाए। सभी को पेंशन - ओपीएस की बहाली, ईपीएफ-95 पेंशनभोगियों को मूल्य सूचकांक के साथ 9,000 रुपये, किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होने वाले सभी लोगों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन।

दस हजार साठ रूपये की समान चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार भेजा न्यायिक रिमांड पर...

-संवाददाता-
वाड्रफनगर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिला के बसंतपुर थाना के अंतर्गत वाड्रगनगर चौकी क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने ठेला दुकान से कराकट काटकर दुकान में रखे दस हजार साठ रूपये के समान चोरी करने वालों चोरों को गिरफ्तार कर चौकी वाड्राफनगर,थाना बसंतपुर में गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ अपराध क्रमांक 209/25 धारा 305,331(3) बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। प्रार्थी अजय यादव पिता स्वर्गीय जवाहर प्रसाद उम्र 44 वर्ष निवासी वार्डफनगर चौकी उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 23/11/25 की रात करीब 9:00 बजे यह बाजार में उपस्थित अपने दुकान ठेला को बंद करके रात करीब 9:00 बजे घर चला गया था दिनांक 25/11/25 को जब यह अपना दुकान ठेला खोला तो देखा की साइड का कराकट काटकर अज्ञात चोर द्वारा इसके दुकान से सरसों तेल रिफाइंड तेल महुआ कीमती 10060 रुपए का चुरा कर ले गए थे, प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी वाड्राफनगर में अपराध क्रमांक 209/25 धारा 305,331(3) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के

दौरान पुलिस ने अज्ञात चोरों की पता तलाश हेतु मुखबिर तैनात किया गया पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि उक्त चोरी की घटना को अंजाम देने वाले मनजीत कुमार कुशवाहा सीताराम प्रकाश कुशवाहा उम्र 25 वर्ष निवासी कोतराही, चंद्रिका कुशवाहा पिता स्वर्गीय तेज बाली कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी कोटराही, संदीप कुमार कुशवाहा पिता ईश्वर दयाल कुशवाहा उम्र 21 वर्ष निवासी बेतो, विशाल कुशवाहा पिता अच्छे लाल कुशवाहा उम्र 20 वर्ष निवासी पेंडारी चोरी की घटना अंजाम देने में शामिल थे, संदिग्धों ने पूछ ताछ में घटना को अंजाम देना कबूला । पुलिस ने संदिग्धों को चौकी वाड्राफनगर लाकर पूछताछ करने पर घटना दिनांक को जुर्म करना स्वीकार किया पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्लास रिंच पाना चोरी किया हुआ महुआ, नगद रकम आदि बरामद किए गया है, अन्य सामान की पताशाजी की जा रही है आरोपियों को आज दिनांक 26/11/25 विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय बलरामपुर में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही है।

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3, जिला-सरगुजा.छ0ग0

रा0प्र0क0 202511022900005/ ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कांति दास पुत्री शिवरतन निवासी ग्राम पचपेडी, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) द्वारा आवेदन श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर लेख किया है कि आवेदिका के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम पचपेड़ी स्थित भूमि ख0न0 213/1, 213/6 रकबा 0.430, 0.079 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेख में पूर्व में वर्ष 2010-11 तक आवेदिका का नाम दर्ज था, वर्तमान में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है। आवेदिका के द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने का निवेदन किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 04/12/2025 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 14/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-3

पिकनिक मनाने मैनपाट गए युवक की कुएं में मिली लाश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक युवक रविवार को बच्चों व ड्राइवर के साथ पिकनिक मनाने मैनपाट गया था। वहां से शाम तक सभी लौट आए थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु की तो उसका कहीं पता नहीं चला। इसी बीच मंगलवार की शाम उसका शव गांव के ही कुएं में तैरता मिला। युवक के सिर पर चोट के निशान देख परिजनों ने कहा कि इसकी हत्या की गई है। पुलिस आत्महत्या व हत्या दोनों ही एंगल से मामले की जांच कर रही है। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुम्हरता निवासी हरेंद्र सिंह 22 वर्ष अपने बच्चे, गांव के कुछ बच्चों और ड्राइवर के साथ वाहन से रविवार को पिकनिक मनाने मैनपाट गया था। मैनपाट में घूमने के बाद शाम तक सभी गांव आ गए थे। ड्राइवर व बच्चे तो घर लौट पहुंच गए, लेकिन हरेंद्र वापस नहीं आया था। जब रातभर वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरु कर दी। रिश्तेदारों के घर भी उसका पता नहीं चला। इसी बीच मंगलवार की शाम करीब 5 बजे कुछ लोगों ने गांव के ही कुएं में उसकी लाश तैरती देखी। इसकी सूचना

मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर दरिमा पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हरेंद्र का शव कुएं से बाहर निकलवाया। उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए दरिमा अस्पताल में रखवाया। बुधवार को पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर मृतक के परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देख उसकी हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसी ने हत्या करने के बाद उसका शव कुएं में फेंक दिया है।

लैब टेक्निशियन को मलेरिया अधिकारी का प्रभार देने पर बवालः चिकित्सकों ने कमिश्नर को सौंपा शिकायत पत्र

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में स्वास्थ्य विभाग के प्रभार वितरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्षेत्र के चिकित्सकों ने कमिश्नर सरगुजा संभाग को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि जिला मलेरिया अधिकारी,नर्सिंग होम एक्ट तथा पीएनडीटी जैसे संवेदनशील और तकनीकी दायित्व एक लैब टेक्निशियन को नियम विरुद्ध तरीके से सौंपे गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि इस नियुक्ति ने न केवल वरिष्ठता सूची और योग्यता मानकों को दरकिनार किया है, बल्कि इससे गंभीर बीमारियों के नियंत्रण से जुड़ी सरकारी मशीनरी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

वरिष्ठता सूची में 135 वें नंबर पर लैब टेक्निशियन,फिर भी मिला

अधिकारी का दायित्व : शिकायत के अनुसार वर्ष 2018 में जारी एलटी वरिष्ठता सूची में राजेश गुप्ता 135 वें स्थान पर हैं, जबकि उनसे वरिष्ठ करीब 25 लैब टेक्निशियन विभाग में पदस्थ हैं। इसके बावजूद वर्ष 2022 में जारी आदेश के आधार पर उन्हें लैब टेक्निशियन की योग्यता होने के बावजूद जिला मलेरिया अधिकारी का दायित्व सौंप दिया गया।

अनुपस्थिति,घर बैठे वेतन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप : पत्र में यह भी उल्लेख है कि राजेश गुप्ता पूर्व में लैब टेक्निशियन रहते हुए नियमित रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं रहते थे, फिर भी उन्हें वेतन मिलता रहा। साथ ही, पीसीपीएनडीटी,नर्सिंग होम एक्ट सहित कई कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी बनकर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगाए गए हैं।

कोरोना काल में भी किया परहेज़...अपनी पहुँच का किया दुरुपयोगः शिकायतकर्ताओं के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा स्वास्थ्य अमला जोखिम उठाकर जनता की सेवा में जुटा था,उस समय भी संबंधित कर्मचारी ने कोरोना जांच से दूरी बनाए रखी। आरोप है कि उस समय भी उसने अपनी पहुँच का उपयोग कर अपने मनमाफिक लोगों को लाभ दिलाया।

योग्यता पर प्रश्न — 'MBBS डॉक्टर मौजूद, फिर MA योग्यता वाले को जिम्मेदारी क्यों?' शिकायत पत्र में यह भी प्रश्न उठाया गया है कि जहां ग्रामीण स्तर तक **MBBS, BDS, BAMS** और **BHMS** डॉक्टर पदस्थ हैं, वहीं **MA** योग्यता रखने वाले लैब टेक्निशियन को मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और जेई जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के नोडल अधिकारी का दायित्व क्यों दिया गया? चिकित्सकों के अनुसार यह निर्णय न केवल अव्यवहारिक है बल्कि चिकित्सा समुदाय में गहरी नाराज़गी का कारण भी बना हुआ है।

राज्य स्तरीय आदेश की जिलों में अवहेलना पर उठे सवाल

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,छत्तीसगढ़ ने 02 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर राजेश गुप्ता को तत्काल मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने निर्देश दिया था। लेकिन शिकायत में कहा गया है कि जिला और संभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से यह आदेश लागू नहीं किया जा सका और वह अभी भी अधिकारी पद पर ही कार्यरत है। सीएमएचओ द्वारा कार्यमुक्त करने के बाद भी उन्होंने विधिक शाखा के लिपिक की मदद से हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

हाई कोर्ट के आदेश का हवाला—सक्षम अधिकारी को दी गई कार्रवाई की स्वतंत्रता : चिकित्सकों ने 2025 के हाई कोर्ट आदेश **CGHC**4992 का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत ने सक्षम अधिकारी को इस मामले में उचित निर्णय लेकर स्थानांतरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

कमिश्नर से हस्तक्षेप की मांग, मिला आश्वासन : सरगुजा संभाग के चिकित्सकों ने कमिश्नर से मांग की है कि नियम विरुद्ध प्रभार तत्काल निरस्त किए जाएं, वरिष्ठता और योग्यता के अनुरूप प्रभार वितरण सुनिश्चित किया जाए और वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई की जाए।

CMYK

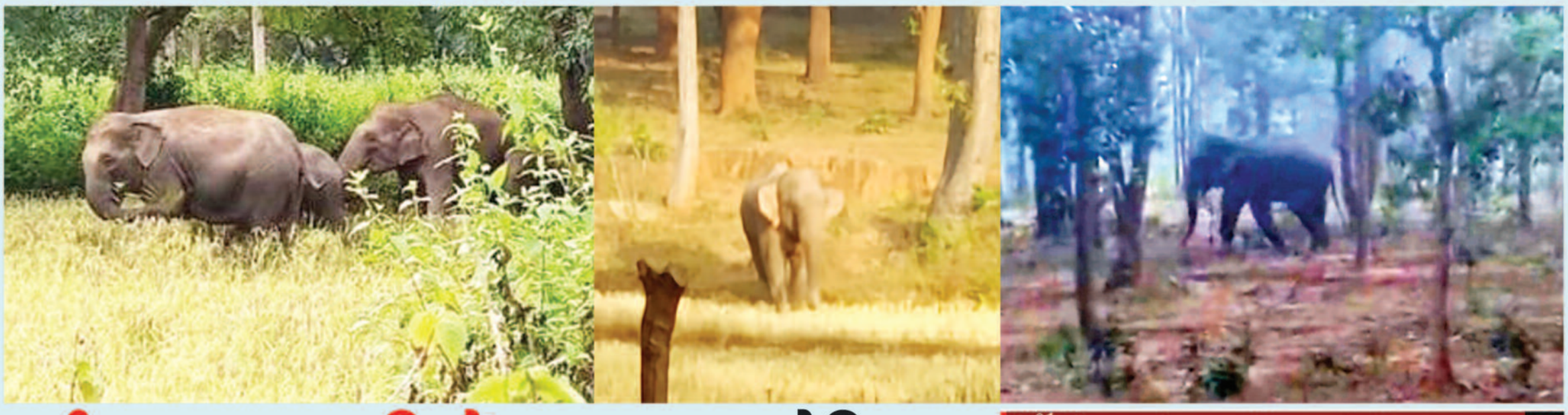

सीमा पर 25 हाथियों का कहर : कोरिया-सुरजपुर के खेत रौंदे,किसानों में हाहाकार!

■ कछाड़ी-जोगिया-मझगवां से किरवाही-घुइडी-छतरंग तक दहशत,रतजगा कर फसल बचा रहे ग्रामीण

■ नुकसान का तात्कालिक आंकलन और क्षतिपूर्ति की मांग तेज,वन विभाग पर सतर्कता बढ़ाने का दबाव

-न्यूज डेस्क-

कोरिया/सुरजपुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

कोरिया-सुरजपुर सीमा क्षेत्र में 25 हाथियों का बड़ा दल किसानों की खड़ी फसलों पर कहर बनकर उतरा है। मौसम की मार से पहले ही परेशान किसान अब हाथियों के उत्पात से तबाह हो रहे हैं। सोमवार व मंगलवार की सुबह भी हाथियों का झुंड मझगवां के जंगल से निकलकर कोरिया मंडल की तरफ बढ़ा और सीमा से लगे खेतों में घंटों तक उत्पात मचाया। विशाल झुंड ने कई किसानों की धान की फसल को रौंदकर चौपट कर दिया।

दोनों जिलों का सीमावर्ती इलाका सबसे अधिक प्रभावित...

कछाड़ी, जोगिया (कोरिया) और किरवाही, घुइडी, छतरंग (सुरजपुर) का पूरा बेल्ट हाथियों के दबाव में है, ग्रामीणों के अनुसार हाथी दिन में जंगल में रहते हैं, शाम ढलते ही खेतों में उतर आते हैं, पूरी रात फसलों को उजाड़ने के बाद सुबह सूर्योदय से पहले फिर जंगल में समा जाते हैं एक साथ 25 हाथियों का दल होने से इनकी निगरानी बेहद मुश्किल है। अंधेरे में जनहानि रोकना वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है।

मूल रूप से यह शांत झुंड,पर फसल तबाही व्यापक

ग्रामीण बताते हैं कि यह झुंड अपेक्षाकृत शांत है,अभी तक जनहानि नहीं हुई, न किसी घर को नुकसान हुआ है लेकिन फसलें पूरी तरह पैरों तले रौंदी जा रही हैं, किसान जगप्रताप,किसान कृष्ण कुमार, सोमरसाय सहित कई ग्रामीणों की फसल भारी मात्रा में नष्ट बताई जा रही है,हाथियों की संख्या 20-25 होने से उनका पेट एक ही खेत में नहीं भरता। यही कारण है कि हाथी 2-3 किमी के दायरे में फैलकर कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

रतजगा कर फसल बचाने में जुटे किसान

ग्रामीण पूरी रात टॉर्च,ढोल और आवाज़ों के सहारे हाथियों को खेतों से दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों का कहना फसल नष्ट हो गई तो साल भर का सहारा खत्म हो जाएगा।

नुकसान का आंकलन कर तत्काल राहत दी जाए:पुष्पेंद्र राजवाड़े

कोरिया जन सहयोग समिति के अध्यक्ष ने दोनों जिलों के वन अधिकारियों से तत्काल सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की,उन्होंने कहा हाथियों ने साल भर की मेहनत बर्बाद कर दी है,प्रभावित किसानों को जल्द राहत मिले।

वन विभाग अभी तक गांवों में नहीं पहुँचा:प्रकाश साहू

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है वन विभाग की टीम को तुरंत मौके पर पहुँच कर मुवायना करना चाहिए। सतर्कता अभियान चलाया जाए और फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति शीघ्र दी जाए।

वन विभाग के लिए चुनौतीः न सर्दी की परवाह,न रात का डर,हाथी लगातार सक्रिय-

कड़ाके की ठंड में भी हाथियों का झुंड रोज शाम को खेतों में उतर रहा है,ग्रामीण भयभीत हैं और वन विभाग पर नज़रदारी बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, अगर झुंड आगे बढ़ा,तो सोनहत-ओड़गी के अन्य गांवों पर भी खतरा मंडराने की आशंका है।

सेमरसोत अभ्यारण्य में तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई,30 हजार की अवैध वनोपज जब्त

संवाददाता-
बलरामपुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सेमरसोत अभ्यारण्य प्रबंधन ने कोदौरा रेंज में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध इमारती लकड़ी और फर्नीचर निर्माण के औज़ारों को जप्त किया है.मुखबिर की सूचना पर की गई इस सटीक कार्रवाई ने क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सूत्रों के अनुसार, घाघरा बीट के ग्राम झलारिया स्थित पटेल पारा में अवैध रूप से लकड़ी संग्रहित किए जाने की सूचना मिलते ही उप निदेशक, एलिफेंट रिज़र्व सरगुजा के निर्देश पर अधीक्षक सेमरसोत अभ्यारण्य बी.एस. भगत के मार्गदर्शन में कोदौरा रेंजर विनय टंडन के नेतृत्व में वन अमले ने छापेमारी अभियान

चलाया। मानिकचंद यादव के घरों की तलाशी ली गई, जहाँ से भारी मात्रा में वन उपज बरामद हुई.जप्त सामग्री में–बीजा लट्ठा : 3 नग,साल चिरान : 24 नग बीजा चिरान : 39 नग के साथ ही फर्नीचर निर्माण में उपयोग आने वाले कई औजार शामिल हैं। वन विभाग ने इस जप्त वन उपज की अनुमानित कीमत 30,000 रुपये आँकी है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध वनोपज को जप्त करने के बाद संपूर्ण कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नियमानुसार की गई। विभाग ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ पीओआर प्रकरण दर्ज कर दिया है तथा समस्त जप्त सामग्री को सुरक्षित रूप से डिपो भेज दिया गया है।

जिला अस्पताल की बदहाली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर का देर रात औचक निरीक्षण,मरीजों से पूछा– समय पर दवाई मिल रही है न?

संवाददाता-
सुरजपुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

जिला अस्पताल की बदहाली और अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायतों ने आखिरकार जिला प्रशासन को सख्त मोड में ला दिया। इन्हीं शिकायतों के बाद कलेक्टर एस. जयवर्धन बीती रात अचानक जिला अस्पताल पहुंचे और करीब एक घंटे तक वार्ड-दर-वार्ड घूमकर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचते ही किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिए बिना स्टाफ से लेकर मरीजों तक से सीधे बातचीत शुरू की और उनसे उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों और उपचार की वास्तविक स्थिति जानी।

मरीजों से सीधा संवाद—'किसी को दवा या इलाज में दिक्कत तो नहीं?

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने भर्ती मरीजों के पलंग तक पहुंचकर उनसे पूछा– **'डॉक्टर समय पर आते हैं? दवाइयां मिल रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं?**

अधिकांश मरीजों ने व्यवस्थाओं पर अपनी-अपनी शिकायतें और अनुभव सामने रखे, जिन्हें कलेक्टर ने गंभीरता से सुनते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण में वार्डों की साफ-सफाई, दवा वितरण प्रणाली, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया।

एसडीएम को दिए सख्त निर्देश-'हर व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग हो'

मौके पर मौजूद एसडीएम शिवानी जायसवाल को कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं की रेग्युलर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शिकायतों को हल्के में लेने का समय अब खत्म हो चुका है और व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद कार्यालय में एसआईआर डिजिटाइजेशन का भी निरीक्षण अस्पताल निरीक्षण के बाद कलेक्टर जयवर्धन ने जनपद कार्यालय सूरजपुर पहुंचकर एसआईआर के तहत चल रहे डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि यह जमीन स्तर तक कामकाज में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल 50.31 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत खैरबार में गौरवपथ निर्माण का किया भूमिपूजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के प्रयासों से सरगुजा जिले में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में अम्बिकापुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खैरबार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत 50.31 लाख रुपए की लागत से 500 मीटर लंबे गौरवपथ सह नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस महत्वपूर्ण भूमि पूजन समारोह में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए ग्रामीण

क्षेत्रों के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाजनक आवागमन, आर्थिक समृद्धि और समग्र विकास सुनिश्चित करने वाली एक प्रमुख योजना है। गौरवपथ और नाली

निर्माण से ग्रामीण इलाकों की सड़कें मजबूत होंगी, जिससे वर्षा के मौसम में आवागमन सुगम होगा। मंत्री ने कहा कि ये प्रयास मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निरंतर जारी हैं और उनके मार्गदर्शन में सरगुजा में कई सड़क निर्माण और विकास कार्य हो रहे हैं।

आंगनबाड़ी में मासूम पर कुत्ते का हमला सुप्रीम कोर्ट निर्देश कागजों में, विभाग खामोश

-संवाददाता-
प्रेमनगर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

सुरजपुर जिले के ग्रामीण अंचल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की सच्चाई एक बार फिर उजागर हो गई है। प्रेमनगर विकासखंड के ग्राम चंद्रनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में दो वर्ष की पण्डो जनजाति की बच्ची पर कुत्ते के हमले ने विभागीय सुस्ती और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। यह घटना उस समुदाय की बच्ची के साथ हुई है जिसे संरक्षित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और जिन्हें परंपरागत रूप से राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र-पुत्री माना जाता है। इतनी संवेदनशील आबादी के बच्चों की सुरक्षा में ऐसी लापरवाही

प्रशासन की गंभीर असफलता को सामने लाती है। गुरुवार सुबह पण्डो पारा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची बालू में खेल रही थी, जबकि केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिका फेस कैप्चरिंग के काम में व्यस्त थीं। इसी दौरान लगभग 12 बजे दोपहर में एक आवारा कुत्ता अचानक झपट पड़ा और बच्ची के दाहिने हाथ पर हमला कर घायल कर दिया। कार्यकर्ता ने कुछ देरी पश्चात उसे प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां रेबीज रोधी टीका लगाया जाना बताया जा रहा है। बच्ची के माता- पिता भूनेश्वरी पण्डो और शनि लाल पांडे ने केंद्र में सुरक्षा के अभाव पर कड़ा आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी परिसर लंबे समय से कुत्तों की आवाजाही की समस्या से जूझ रहा है,लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। केंद्र के चारों ओर बाउंड्री नहीं होने से यह क्षेत्र जानवरों के लिए खुला मैदान बना हुआ है। सवाल उठ रहा है कि जब संरक्षित जनजाति के बच्चों के लिए भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं है।

विधायक शकुंतला पोर्ते का जाति विवाद गहराया, खुद सामने आकर आरोपों को नकारा कांग्रेस बोली एसडीएम पर हो एफआईआर...

-संवाददाता-
प्रतापपुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र विवाद में मंगलवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। विधायक ने स्वयं मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने आधिकारिक दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि

सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने होगी, जबकि दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं ने तत्कालीन एसडीएम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस चौकी में ज्ञापन सौंपा है।

प्रशासनिक दस्तावेज में पिता और पति दोनों का उल्लेख..: विधायक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि उनका जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा 11 जुलाई 2001 को दायरा पंजी क्रमांक 671/ब-121/2001-02 में दर्ज करके जारी किया गया था। प्रशासनिक दस्तावेजों में इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रमाण पत्र में पिता और पति दोनों के विकल्प दर्ज हैं विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने दस्तावेजों की प्रतियां मीडिया को सौंपते हुए कहा : 'हमारे द्वारा सभी प्रमाण सही और विधिसम्मत तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ' उन्होंने सूक्ष्म और गहन जांच की मांग जिला समिति से की है। उन्होंने जाति सत्यापन समिति के पूर्व अध्यक्ष के सामने अनुपस्थित रहने के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सभी नोटिसों का विधिवत जवाब दिया गया है।

कांग्रेस नेता बोले : एसडीएम पर हो एफआईआर.. इसी तरह, इस मामले के शिकायतकर्ता मंगलवार को बड़ी संख्या में वाड्रफनगर पुलिस चौकी पहुंचे। कांग्रेस नेता शिवभजन सिंह मरावी ने कहा कि निर्वाचन नामांकन के दौरान भी उन्होंने इस पर आपत्ति लगाई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कुछ नहीं हो सका।

युवक पर चाकू से जानलेवा हमले में 7 के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)।

खरसिया नाका के पास मुरादाबादी बिरयानी दुकान में बिरयानी लेने गए युवक के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने सात नामजद सहित अन्य के विरूद्ध बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। अविनाश राय ने पुलिस को बताया है कि वे खरसिया नाका में स्थित बिरयानी दुकान गए थे,इस दौरान गोलू पठान, फैजान खान, फैजान सिद्दीकी, साहिल खान,अजमत पठान,फरहान सिद्दीकी,अहमद शेख एवं इनके अन्य साथी आए और नाम पूछने लगे। तीनों अपना नाम बताए,इसके बाद सभी आदर्श साहू से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और हाथ, मुक्का, चाबी, कड़ा से मारपीट करने लगे। गोलू पठान के द्वारा चाकू से आदर्श साहू के सिर में वार किया गया, जिससे खून बहने लगा। हमलावरों के जाने के बाद वह अपने दोस्त साहिल गुप्ता के साथ आदर्श साहू को मोटरसायकल में बैठाकर जिला अस्पताल ले गया।

अविनाश राय की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 109, 115(2), 191(2), 191(3), 296, 351(3) का मामला दर्ज कर लिया है।

CMYK

जिला खनिज न्यास का 'अमर लिपिक'

जिला खनिज न्यास शाखा का लिपिक वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे

क्या 'फेविकोल मॉडल' पर चल रहा है सिस्टम?

संपत्ति, संरक्षण,पुरानी भर्ती और चोरी प्रकरण पर उठ रहे गंभीर सवाल

-रवि सिंह-

कोरिया,26 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

जिला खनिज न्यास शाखा में वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे लिपिक टेकचंद साहू को लेकर बड़े आरोप और गहरी चर्चाएँ सामने आ रही हैं, स्थानीय लोगों और विभागीय सूत्रों के अनुसार, लिपिक की लंबे समय से एक ही जगह जमे रहने को लेकर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी अदृश्य संरक्षण की वजह?

धन्ना सेठ लिपिक...कार्यालय में चर्चा का विषय

कई कर्मचारियों का कहना है रहन-सहन किसी बड़े कारोबारी जैसा,गाड़ियों-कपड़ों से लेकर खर्च तक सबकुछ वेतन से बाहर का लगता है,प्रशासनिक संरक्षण मिले बिना ऐसा संभव नहीं,यह बयान कर्मचारियों द्वारा दिया गया है,नाम प्रकाशित नहीं किया जा रहा।

आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई तो बड़ा खुलासा संभव?

स्थानीय नागरिकों का कहना है, यदि आय से अधिक संपत्ति की जांच लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या आर्थिक अपराध शाखा से हो जाए, तो बड़ा मामला खुल सकता है।

अधिकारियों की चुप्पी... क्या सुविधा वाला स्टाफ इसलिए नहीं हटाया जाता?

सबसे बड़ा सवाल वर्षों से एक ही पोस्ट, न तबादला, न जिम्मेदारी में बदलाव, न जांच, न विभागीय अनुशासन इसे लेकर जिले में चर्चा है कि क्या यह लिपिक अधिकारियों के लिए 'सुविधाजनक' बना हुआ है?

विशेष टिप्पणी...

यह रिपोर्ट सूत्रों,कार्यालय चर्चाओं और उपलब्ध दस्तावेज़ीय संकेतों पर आधारित है, दैनिक घटती-घटना इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता,यदि जिला प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा जांच आरंभ की जाती है,तब वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

समाप्ति में...

व्यक्ति नहीं व्यवस्था सवालों के घेरे में है, यदि एक लिपिक वर्षों तक एक कुर्सी पर टिककर, पूरे विभाग पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रख सकता है, तो इसे 'दफ़्तर संस्कृति' नहीं, प्रशासनिक कमजोरी कहा जाएगा, कोरिया की जनता पारदर्शिता चाहती है, और पारदर्शिता केवल एक ही से आती है...जांच से, पूछा जाना ही पहला कदम है जवाबदेही की ओर।

पाठकों से सवाल...

क्या जिला खनिज न्यास शाखा की सम्पूर्ण व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए?
अपनी राय हमारे संपादक को भेजें।

व्यवस्था यही है?

- जिला खनिज न्यास का अमर लिपिक...कुर्सी पर वर्षों से जमे, संपत्ति पर उठे बड़े सवाल
- धन्ना सेठ लिपिक का राज! न तबादला,न जांच...आखिर कौन दे रहा संरक्षण?
- खनिज शाखा का असली कलेक्टर कौन?...लिपिक की संपत्ति,चोरी प्रकरण और पुराने घोटालों पर उठे सवाल
- सरकारी वेतन या 'खास कमाई'?- लिपिक की आलीशान लाइफस्टाइल ने खोले करोड़ों के रहस्य
- जिला प्रशासन की चुप्पी क्यों?- एक लिपिक पर कार्रवाई न होना पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है'

एक लिपिक, एक कुर्सी... और पूरा तंत्र? कोरिया में खनिज न्यास शाखा की 'अदृश्य सत्ता' पर मौन क्यों?

कोरिया जिले में जिला खनिज न्यास शाखा से जुड़ा एक सवाल पिछले कई वर्षों से अनुत्तरित है एक लिपिक को हटाने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं जुटा पाते अधिकारी? हमारा सवाल किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि तंत्र की संरचना, सिस्टम की कमजोरी, और जवाबदेही की कमी पर है।

वर्षों से एक ही कुर्सी: जिले में चर्चा

क्या इस कुर्सी पर फेविकोल लगा है?

जिला अधिकारियों के कई कार्यकाल बदल गए, पर इस एक लिपिक की कुर्सी नहीं बदली, सूत्रों का सवाल कौन-सी शक्ति है जो इस लिपिक को इस शाखा से हटने नहीं देती?

क्या वाकई एक लिपिक इतना शक्तिशाली हो सकता है?

सवाल यही है यदि एक लिपिक वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ रहे, फाइलों,प्रक्रियाओं और निर्णयों में प्रभाव रखे, और प्रशासन उसका तबादला तक न कर पाए, तो क्या यह व्यक्ति की क्षमता है या सिस्टम की निर्बलता? यदि यह केवल प्रशासनिक आवश्यकता होती, तो इतने वर्षों तक तबादला न होना संयोग नहीं कहा जा सकता।

संपत्ति और रहन-सहन पर उठती चर्चाएँ...क्या सिर्फ चर्चा मानकर छोड़ दिया जाए?

जिले में चर्चा है कि एक लिपिक का रहन-सहन,उसके वेतन के अनुपात से कहीं अधिक है,यह आरोप प्रमाणित नहीं हैं, परंतु यदि चोरी की घटना हो और एफआईआर न हो,तो सवाल तो उठेंगे ही, क्यों नहीं हुई एफआईआर? क्यों नहीं हुई विभागीय जांच? क्यों नहीं हुई संपत्ति का सत्यापन? यदि इन सवालों पर प्रशासन चुप है,तो चुप्पी भी एक उत्तर है और वह उत्तर बहुत कुछ कहता है।

खनिज न्यासः सबसे संवेदनशील विभाग...लेकिन निगरानी सबसे कम

जिला खनिज न्यास की राशि कोई सामान्य बजट नहीं,यह वह पैसा है जो खनिज क्षेत्र के विकास, जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित है, यदि इसी शाखा में प्रक्रियाओं पर अनौपचारिक नियंत्रण या एक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता,जैसी स्थिति बने,तो जोखिम केवल वित्तीय नहीं,लोकतांत्रिक और प्रशासनिक दोनों हैं।

2014 भर्ती परीक्षा...अधूरे सवालों का पुराना पन्ना

यदि किसी भर्ती परीक्षा पर प्रश्नचिह्न लगें,और उसमें वही नाम सामने आए जिसका वर्तमान में विवाद चल रहा हो, तो जांच का क्षेत्र और व्यापक हो जाता है, सवाल यह नहीं कि आरोप सही हैं या गलत, सवाल यह है जांच क्यों नहीं हुई? और जांच से बचने का लाभ किसे मिलता है? वर्षों से तबादला न होना, क्या यह 'सुविधा का तंत्र' है? प्रशासन में बार-बार चर्चा रही है कि कुछ कर्मचारी कुछ पदों पर सुविधाजनक होते हैं उनके रहते काम जैसा चलना चाहिए वैसा चलता है, लेकिन, सवाल यह है किसके लिए सुविधाजनक? और किस कीमत पर?

जिला प्रशासन की चुप्पी...

अब जनता सवाल पूछ रही है...

जब जिले के लोगों में यह सवाल उठने लगे,क्या लिपिकों की सत्ता, अफसरों से भी ऊपर है? तो यह केवल अफवाह नहीं, सिस्टम की विफलता का संकेत है, लोकतंत्र में एक लिपिक का अप्रभावित और अपरिवर्तित बने रहना किसी भी स्वस्थ प्रशासन का संकेत नहीं हो सकता,समाधान जांच,पारदर्शिता और जवाबदेही, यदि प्रशासन चाहता है कि जिले का विश्वास बना रहे, तो उसे आय से अधिक सम्पत्ति जांच,खनिज न्यास शाखा का ऑडिट,पदस्थापना और तबादला नीति की समीक्षा, पुराने मामलों की पुनःसमीक्षा, लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू से स्वतंत्र जांच जैसे कदमों पर विचार करना होगा।

करोड़ों की संपत्ति का आरोप... वेतन से 'कहीं अधिक' बताई जा रही धन-सम्पत्ति...रॉयल है जीवनशैली

सूत्रों का दावा है कि इस लिपिक ने वर्षों में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की,जीवनशैली उच्च वर्ग जैसी,वाहन,मकान,जेवर और लेनदेन पर सवाल कई सहकर्मी कहते हैं सिर्फ वेतन से इतना संभव नहीं घटती-घटना इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करती, लेकिन चर्चा का माहौल गर्म है।

खनिज मद की फाइलें,राशि और प्रक्रिया पर 'अत्यधिक प्रभाव' का आरोप

कुछ सूत्रों का कहना है कि खनिज न्यास की राशि, फाइल संचालन, और उपयोग प्रक्रिया में इसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा है, यह आरोप भी स्वतंत्र पुष्टि की प्रतीक्षा में है, लेकिन जिले में यह विषय व्यापक चर्चा में है।

घर में चोरी,लेकिन एफआईआर न कराना,शहर में सबसे बड़ा सवाल

कुछ माह पूर्व लिपिक के घर में चोरी हुई, संवेदनशील बात, सूत्रों के अनुसार, लाखों की चोरी होने के बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, चर्चा यह भी है कि यदि एफआईआर होती तो अवैध संपत्ति का खुलासा हो सकता था, इसलिए मामला दबा दिया गया।

भरी पंचायत में महिला और युवक का मुंह किया काला, फिर पहनाई जूतों की माला,3 बच्चों की मां का अफेयर

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,26 नवंबर 2025 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहां 3 बच्चों की मां व 1 बच्चे के पिता के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इसकी खबर जब महिला के पति को हुई तो विवाद होने लगी। 21 नवंबर को इसी बात पर पति ने उसे घर से निकाल दिया तो पड़ोस में ही रहने वाले प्रेमी के घर चली गई। इसके बाद महिला के चाचा ससुर व सास ने दोनों को पकड़कर गांव में पंचायत बैठाई और भरी सभा में उनका मुंह काला कर जूतों की माला पहनाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। एमसीबी जिला निवासी एक महिला की 8 वर्ष पूर्व भरतपुर विकासखंड के ग्राम बरेल में शादी हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोस में ही रहने वाले ओमप्रकाश पनिका से प्रेम संबंध चल रहा था। ओमप्रकाश भी एक बच्चे का पिता है। युवक से अफेयर की बात पर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था।

नाम परिवर्तन सूचना

खगेश्वर कुमार, पिता गोपाल राम भगत, उम्र 42 वर्ष,पेशा-नौकरी, पता- महामाया पारा, वार्ड क्रमांक-03,रतनपुर,जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ –

मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम खगेश्वर प्रसाद भगत अंकित हो गया है, जब कि मेरे कक्षा- 8वी की अंकसूचरी में मेरा नाम खगेश्वर कुमार भगत अंकित है।

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ – मेरे सभी दस्तावेजों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, एवं पुलिस आई0डी0 कार्ड में मेरा नाम खगेश्वर कुमार अंकित है।

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ – मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम खगेश्वर प्रसाद भगत त्रुटिवश अंकित हो गया है। उसके स्थान पर मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम खगेश्वर कुमार भगत अंकित किया जावे तथा समस्त दस्तावेजों पर मेरा नाम अथवा शासकीय पत्राचार करते समय मेरा नाम खगेश्वर कुमार भगत अंकित किया जावे।

शपथकर्ता
खगेश्वर कुमार भगत

न्यायालय नायब तहसीलदार दरिमा, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0... /अ-6/25-26
ग्राम- कंठी तहसील- दरिमा

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता कि- आवेदक उमेश्वर राजवाड़े आ0 बहादुर राजवाड़े जाति रजवार निवासी ग्राम मानिकप्रकाशपुर थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम कंठी प0ह0न0 03 रा0नि0म0 सोहगा तहसील दरिमा में स्थित भूमि ख0न0 100/1, 105/2, 110, 115, 122/1, 156, 164, 165, 221/2, 222/2, 323, 558, 1257/2, 1258/2, 1259, 1263 रकबा 0.129, 0.234, 0.125 0.821 0.340, 0.291, 0.113, 0.077 हे0 भूमि का बी-1 एवं वर्तमान भूमि स्वामी बुधराम राजवाड़े की मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दिनांक 03/04/2025 को की गयी पंजीकृत वसीयत नामा (अंतिम इच्छा - पत्र) की छाया प्रति संलग्न कर पंजीकृत वसीयत नामा (अंतिम इच्छा - पत्र) के आधार पर वाद भूमि में से आवेदक के नाना बुधराम को प्राप्त उसकी हिस्से की भूमि पर से राजस्व अभिलेख में मृतक का नाम विलोपित कर आवेदक का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्राप्त है।

अतः उपरोक्त संबंध मे जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत किसी भी का दावा / आपत्ति प्राप्त होने पर इस पर विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 19/11 / 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा द्वारा जारी किया जाता है।

सील
नायब तहसीलदार
दरिमा

न्यायालय तहसीलदार लटोरी, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0.202511260100020/ अ-21/2025-2026

ईश्तहार

बिन्देश्वरी प्रति वर्षा जायसवाल
सर्व साधारण ग्रामवासी

ग्राम संजयनगर तहसील लटोरी को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बिन्देश्वरी पति स्व0 विरेन्द्र मण्डल निवासी ग्राम संजयनगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने खाते की भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम संजयनगर तहसील लटोरी जिला सूरजपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 118/1 रकबा 0.410 है0 भूमि को अनावेदिका क्रेता श्रीमती वर्षा जायसवाल पति योगेन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम संजयनगर तहसील नटोरी जिला सूरजपुर के पास 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रूपये) में विक्रय करने हेतु मौदा तय किया गया है। आवेदित भूमि पुर्नवास विभाग से शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु अनुमति बाबत आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय सूरजपुर को प्रस्तुत करने से जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण प्रारम्भ किया गया।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 15-12-2025 को उपस्थित हो कर दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। इस तिथि के बाद में प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 26-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया जाता है।

तहसीलदार
सील लटोरी जिला-सूरजपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो0नि0वि0 वि/यां संभाग रायपुर छ.ग.

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-9996/NIT-13/2025-2026/ व ले लि दिनांक : 21/11/2025

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम No Of Calls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3
13T0140	लो.नि.वि. (वि./ यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग में स्थापित एयर कंडीशनिंग हेतु संधारण/मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण	10.00
13T0141	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग के आवासीय भवनों में स्थापित वाटर पंप - सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, प्रेशर पंप इत्यादि हेतु संधारण / मरम्मत का कार्य । प्रथम आमंत्रण	3.50
13T0142	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग के गैर आवासीय भवनों में स्थापित वाटर पंप-सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, प्रेशर पंप इत्यादि हेतु संधारण / मरम्मत का कार्य । प्रथम आमंत्रण	1.50
13T0143	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग में स्थापित एल.ई.डी. साइन बोर्ड हेतु संधारण/मरम्मत का कार्य । प्रथम आमंत्रण	1.20
13T0144	लो.नि.वि.(वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग के गैर आवासीय भवनों में स्थापित सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, डेजर्ट कूलर, गीजर, इत्यादि हेतु संधारण / मरम्मत का कार्य । प्रथम आमंत्रण	2.50
13T0145	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग के आवासीय भवनों में स्थापित सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, डेजर्ट कूलर, गीजर, इत्यादि हेतु संधारण / मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण	1.00
13T0146	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग के गैर आवासीय भवनों में स्थापित विद्युत् कण्ट्रोल पैनल, स्विच गियर, केबलिंग इत्यादि हेतु संधारण / मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण	2.50
13T0147	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग के आवासीय भवनों में स्थापित विद्युत् कण्ट्रोल पैनल, स्विच गियर, केबलिंग इत्यादि हेतु संधारण / मरम्मत का कार्य प्रथम आमंत्रण	2.00
13T0148	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग में स्थित आवासीय भवनों में विद्युतीकरण संधारण / मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण	5.20
13T0149	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग में स्थित गैर आवासीय भवनों में विद्युतीकरण संधारण /मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण	9.80
13T0150	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग में स्थापित 10, 25 एवं 200 के. वी. ए. क्षमता के 05 डी. जी. सेटों का रखरखाव / संधारण का कार्य। प्रथम आमंत्रण	5.00
13T0151	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग कर्मशाला रायपुर के अंतर्गत सिरपुर भवन एवं सिविल लाइन अनुभाग में स्थापित 10, 25 एवं 200 के. वी. ए. क्षमता के 05 डी. जी. सेटों का रखरखाव / संधारण का कार्य प्रथम आमंत्रण	5.00
13T0152	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, गीजर एवं अन्य विद्युत् उपकरणों का वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य । प्रथम आमंत्रण	8.00
13T0153	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत न्यू कन्वेंशन हॉल एवं नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में स्थापित लिफ्ट का वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य । प्रथम आमंत्रण	8.00
13T0154	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में लगे हुए डी. जी. सेट का वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य। प्रथम आमंत्रण	7.50
13T0155	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन के कन्वेंशन हॉल, कांफ्रेंस हॉल एवं मिनी कांफ्रेंस में ऑडियो विडियो व एल.ई.डी. वाल सिस्टम का वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य । प्रथम आमंत्रण	9.20
13T0156	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में यू.पी.एस., इन्वर्टर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य। प्रथम आमंत्रण	5.90
13T0157	लो.नि.वि. (वि./यां.) उपसंभाग विधानसभा रायपुर अंतर्गत नवीन विश्राम भवन सिविल लाइन रायपुर में अग्निशामक यंत्र का वार्षिक रिफिलिंग एवं रखरखाव का कार्य । प्रथम आमंत्रण	2.80

नोट- निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी दिनांक 05/12/2025 अपरान्ह 5:30 बजे तक निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

शर्तें- 1) उपरोक्त कार्यों के आबंटन प्राप्त होने पर ही नियामानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

जी नंबर-252604988/4

कार्यपालन अभियंता
लो0 नि0 वि0 वि/यां संभाग रायपुर छ ग

» पीएम आवास कहीं और...अवैध निर्माण कहीं... वन विभाग की कार्यवाही के बाद कांग्रेस के निशाने पर स्थानीय मंत्री

» क्या कांग्रेस के कुछ नेता पीड़ितों का दर्द बाँटने नहीं,बल्कि मंत्री को घेरने की राजनीतिक स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे थे?

» झूठे नैरेटिव का बुलडोज़र...पीएम आवास नहीं, अवैध कब्जे गिरे...

» राजनीति की स्क्रिप्ट तैयार,सच आया तो पूरा प्लान फ्लॉप...

» तीन-तीन नोटिस की रिसीविंग के बाद भी 'पीड़ित' बनाने का खेल...

» वन विभाग की कार्रवाई,मंत्री पर निशाना: दुख कम,राजनीति ज्यादा...

» अवैध कब्जा हटते ही नेताओं का दर्द क्यों जागा?

» वन विभाग की कार्रवाई की हीरो शिप किसकी–विभाग के अफसरों की या फिर मंत्री के निजी आवास पर भीड़ लगाना ही राजनीति का 'शॉर्टकट'?

पट्टा नहीं, पीएम आवास नहीं...

फिर भी 'बेघर-आदिवासी' की झूठी कहानी क्यों?

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,26 नवंबर 2025 (घटती-घटना)। बीते दिनों वन विभाग ने रतनपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हटाते हुए तीन दुकान और एक कच्चा-मकान जमींदोज किया, कार्यवाही पूरी तरह नोटिस-आधारित थी, लेकिन कुछ राजनीतिक चेहरों ने इसे आदिवासी बेघर, पट्टे की जमीन तोड़ी और पीएम आवास गिराया जैसे आरोपों के साथ घेराबंदी में बदलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर जब मीडिया का पूरा दल मौके पर पहुँचा, तो तस्वीर पूरी तरह उलट निकल आई।

अवैध कब्जे का सच–और राजनीति का झूठा प्रायश्चित यदि बता करे रतनपुर की घटना यह भी बताती है कि दिल्लीङ्करायपुर की राजनीति से ज्यादा खतरनाक है गांव की छोटी राजनीति, जहाँ सच्चाई की मौत भी चुपचाप हो जाती है और झूठ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सीधे मंत्री के घर तक पहुँच जाता है, सवाल यह नहीं कि अवैध कब्जा क्यों तोड़ा गया सवाल यह है कि अवैध कब्जाधारियों को राजनीतिक छतरी किस कीमत पर मिली? जिस मंत्री को निशाने पर लिया गया, उनकी भूमिका शून्य। कार्रवाई वन विभाग की; नोटिस वन विभाग के; जमीन वन विभाग की; और फायदा लेने की कोशिश नेताओं की, यह वही राजनीति है जो पीड़ित को 'पीड़ित' नहीं बनने देती, पहले उसे अपनी पार्टी की प्रॉपर्टी बनाती है, फिर उसके कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता पर निशाना साधती है, और यह भी याद रखा जाए–जब झूठ को सच की तरह सजाया जाता है, तब असली पीड़ित कानून नहीं, समाज होता है, वन भूमि बचाने के नाम पर लड़ाई बहुत कम लोग लड़ते हैं, लेकिन वन भूमि कब्जाने वालों की पैरवी करने वाले अचानक 'क्रांतिकारी' बन जाते हैं, क्योंकि भीड़ सच्चाई नहीं पूछती वह सिर्फ नारा देखती है, रतनपुर मामले ने एक कड़वा सच सामने रखा है यदि राजनीतिक फायदे के लिए अवैध कब्जे को भी 'आदिवासी अधिकार' जैसी पवित्र आवाज़ के साथ जोड़कर बेचा जा सकता है, तो फिर आने वाले वर्षों में अफसर काम करने से डरेंगे और नेता ट्वीट करने का साहस बढ़ाएँगे। सबसे बड़ा अपराध क्या है?–अवैध कब्जा? या अवैध कब्जे को सामाजिक न्याय के नाम पर धोकर परोस देना? इस सवाल का जवाब रतनपुर में मिला है–और वह किसी को अच्छा नहीं लगेगा, यह राज्य का दुर्भाग्य नहीं, राजनीति का चेहरा है।

राजनीतिक रंग क्यों चढ़ा? स्थानीय मंत्री को घेरने की कोशिश

स्थानीय मंत्री के गृह ग्राम से जोड़कर कुछ नेताओं ने इसे मंत्री बनाम आदिवासी का रूप देने की कोशिश की, जबकि कार्यवाही पूरी तरह वन विभाग की है, नोटिस विभाग ने जारी किए, अवैध कब्जे वन भूमि पर थे, बेघर-आदिवासी नैरेटिव फर्जी निकला तो सवाल बनता है, क्या कुछ नेता सिर्फ मंत्री को घेरने के लिए पीड़ितों के कंधे पर राजनीति की बंदूक रख रहे थे?

वन विभाग...अवैध कब्जा हटाना मजबूरी... और कई जगह चिन्हांकित हैं...

विभाग ने कहा कई नोटिस के बाद भी कब्जाधारी नहीं हटे,तब कार्रवाई की गई, और भी कई अतिक्रमण चिन्हांकित हैं कार्रवाई आगे भी होगी।

झूठ का राजनीतिक खेल–वन विभाग की वैध कार्यवाही को मोड़ने की कोशिश

ग्राम वासियों के बयान,नोटिस,मौके की जांच,विभागीय कागज सब मिलकर दिखाते हैं कि अतिक्रमण हुआ,नोटिस दिए गए,मकान-दुकान गैरकानूनी थे,पीड़ित मूल निवासी नहीं,बेघर होने की बात फर्जी,राजनीति का नैरेटिव सच से बिल्कुल उलट कुछ लोग राजस्व/वन विभाग की वैध कार्यवाही को मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तथ्यों ने उनकी कहानी ढहा दी।

रतनपुर की घटना एक आइना है जहाँ सच साफ दिख रहा है...

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल का कहना है की वन विभाग की कार्रवाई को स्थानीय मंत्री से जोड़ना, राजनीति की वही पुरानी स्क्रिप्ट है तथ्य गायब, नैरेटिव हाज़िर, सवाल यही है कि नेताओं को पीड़ित के घर से ज़्यादा मंत्री का घर क्यों दिखा? जब राजनीति सच से बड़ी हो जाए तो अवैध कब्जाधारी भी रातों-रात 'आदिवासी पीड़ित' बना दिए जाते हैं, रतनपुर की घटना एक आइना है जहाँ सच साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग धुंध फैलाने पर उतारू हैं।

» राजनीति बनाम हकीकत: ज़मीन पर पहुँची मीडिया टीम, खुलासा चौंकाने वाला...

» जमीन वन विभाग की...शिकार स्थानीय मंत्री क्यों? राजनीति का एक्सीडेंट...

घटती घटना | कोरिया- सूरजपुर समाचार | अम्बिकापुर,बुधवार 26 नवम्बर 2025 | 5

गरीब-आदिवासियों के घर उजाड़े,प्रशासन दिनभर गायब...राहत के लिए मंत्री बंगले तक पहुँची कांग्रेस

सुबह बुलडोजर...रात तक न टेंट,न भोजन...आधी रात मंत्री आवास पर कांग्रेस का घेराव

अधिकारियों ने फोन तक न उठाया कांग्रेस बोली: भाजपा संरक्षण में चल रहा वन विभाग का बुलडोजर राज

एसपी के हस्तक्षेप तक खुले आसमान में तड़पते रहे पीड़ित, कांग्रेसी नहीं हटे,जब तक राहत नहीं मिली...

कांग्रेस का हमला: वन विभाग नेताओं के इशारे पर चलता है...गरीबों पर कार्रवाई, बड़े कब्जाधारियों पर चुप्पी

मंत्री के बंगले के सामने घंटों सड़क पर बैठे पीड़ित कांग्रेसी

एसपी के हस्तक्षेप के बाद देर रात मिली राहत

गरीबों के घर तोड़कर फरार हुए अधिकारी,राहत दिलाने के लिए मंत्री बंगले तक जाना पड़ा

एसपी के हस्तक्षेप तक प्रशासन 'बंद कमरे' में छिपा रहा

वन विभाग की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ

कांग्रेस का आधी रात धरना-हंगामा

कांग्रेसी पहुंचे मौके पर, अधिकारी पूरे दिन 'गायब'

आधी रात मंत्री बंगले के बाहर धरना, पुलिस-प्रशासन बेचैन

एसपी के निर्देश पर रात में ही टेंट, भोजन-रहने की व्यवस्था

कांग्रेस का गंभीर आरोप वन विभाग भाजपा नेताओं के संरक्षण में,गरीबों पर सीधा अत्याचार

सुबह बुलडोजर,रात तक न भोजन न रहने की व्यवस्था

कांग्रेस की मांग या समान कार्रवाई करो या तुरंत मुआवजा दो,दोहरा कानून नहीं चलेगा

प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोग उजाड़ रहे आदिवासियों का घर-गुलाब कमरो

बड़ा खुलासा-1

जिस 'पट्टे' की दुहाई–वह जमीन पर मकान था ही नहीं...

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फैलाया गया झूठ यही था कि करीमन के पट्टे वाली जमीन पर बने घर को तोड़ दिया गया, लेकिन मौके पर मिला सच करीमन की पट्टे वाली जमीन पर कोई घर बना ही नहीं था, जिस घर को सुशीला ने करीमन ने जगह दी ये कहकर बताया,वह पूरी तरह वन विभाग की जमीन पर पाया गया, सुशीला बोली करीमन ने कहा यह उनकी पट्टे की जमीन है, हमने घर बना लियाज्सौदा हुआ था या पैसा लिया गया? इस पर सुशीला ने कहा यह मेरे पति बताएँगे, यानी पट्टे तोड़ा गया पूरी तरह फर्जी नैरेटिव!

बड़ा खुलासा-2

बेघर?–नहीं... सबके पास दूसरी पंचायत में पक्के मकान मौजूद

जिस सुलेमान को बेघर बताकर भावनात्मक कार्ड खेला गया, वह कोड़ांगी में पहले से पक्का मकान वाला निकला, सरपंच, स्थानीय लोगों और तथ्यों से साफ हुआ, कोई भी मूल निवासी नहीं, यहाँ वोटर-लिस्ट में नाम तक नहीं, कई लोगों पर मकान बनाकर बेचने का धंधा करने का भी आरोप, मतलब–आदिवासी बेघर जैसी बातें सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने के लिए फैलाई जा रही थीं।

बड़ा खुलासा-3

नोटिस नहीं दिया गया?- तीन-तीन नोटिस की रिसीविंग मौजूद

वन परिक्षेत्राधिकारी शंखमुनि पांडे के अनुसार 03 सितम्बर 2024, 21 अगस्त 2025 व 17 सितम्बर 2025 नामित अतिक्रमणकारियों ने राजेंद्र प्रधान, सुलेमान/नागेंद्र और रामप्रसाद को तीन नोटिस दिए गए, रिसीविंग विभाग के पास मौजूद है, अर्थात बिना नोटिस बुलडोज़रभी मनगढ़ंत कहानी!

बड़ा खुलासा-4

पीएम आवास तोड़ने का दावा भी फर्जी

सरपंच नरेंद्र सिंह ने साफ कहा रतनपुर में ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पर पीएम आवास है ही नहीं, जिसका घर वन विभाग ने तोड़ा, हाँ एक पीएम आवास पहले से ही अवैध था खड़गवां के नाम पर स्वीकृत, रतनपुर में बनाया गया जिस पर जनपद पहले ही नोटिस जारी कर चुका था, उस जगह पर वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ÷पीएम आवास तोड़ दिया गया–पूरी तरह गलत सूचना।

बड़ा खुलासा-5

रामप्रसाद-यहाँ का नहीं, सूरजपुर जिले का निवासी

पीड़ित लिस्ट में शामिल नामों की जांच में सामने आया रामप्रसाद तो रतनपुर का निवासी भी नहीं, वह सूरजपुर जिले का रहने वाला है यानी इस अतिक्रमण ग्रुप का स्थानीय जमीन से कोई संबंध नहीं, फिर भी राजनीतिक नैरेटिव में इन्हें 'मूल निवासी आदिवासी' बताया जा रहा था।

स्थानीय लोगों की राय: 'ये हाल के वर्षों में आए,पहचान बाद में बनी...मूल निवासी नहीं...

स्थानीय ग्रामीणों के बयान बेहद स्पष्ट

» 'यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं।'

» 'पिछले वर्षों में कब्जा किया गया।'

» 'एक व्यक्ति कई घर बनाकर बेचता है।'

» 'पीएम आवास, पट्टा–सब फर्जी दावा।' यानी पूरी राजनीति एक झूठी कहानी पर खड़ी।

सांसद प्रतिनिधि रुद्र साहू ने धान खरीदी केंद्रों का लिया जायजा,किसानों की समस्याओं से हुए अवगत

डीएपी यूरिया की कमी पर जताई गंभीर चिंता,कहा खाद उपलब्धता जल्द सुनिश्चित कराएंगे...

-संवाददाता-

सोनहत,26 नवंबर 2025 (घटती-घटना)। सांसद प्रतिनिधि रुद्र साहू ने कटगोड़ी व सोनहत क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया,रुद्र ने मौके पर मौजूद किसानों से फसल तुलाई, ट्रक-लिफ्टिंग, चेक-पेमेंट और रकबा कटौती से जुड़ी समस्याएँ विस्तार से सुनीं, उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। कोई भी समस्या हो–मुझे सीधे अवगत कराएं, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ।

रकबा कटौती की शिकायत–रुद्र ने दिलाया समाधान का भरोसा...कुछ किसानों ने अपने रकबे कटने की शिकायत की। इस पर रुद्र साहू ने कहा तहसील कार्यालय में सम्पर्क कर कटे हुए रकबे फिर से जोड़ा जाएगा,जिस किसान का रकबा गलत तरीके से घटा है, उसे न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है उन्होंने प्रभारी प्रबंधकों से खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू रखने और किसानों की परेशानी दूर करने का निर्देश भी दिया।

डीएपी-यूरिया की भारी किल्लत,रुद्र ने जताई चिंता-रुद्र साहू ने किसानों की सबसे गंभीर समस्या उठाई डीएपी खाद की कमी, उन्होंने कहा समितियों में आपूर्ति कम और किसानों की मांग बहुत अधिक है। रबी फसल का सीजन आधा बीत चुका है, ऐसे में खाद न मिलना किसानों के लिए संकट बन गया है, किसान लगातार समितियों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जरूरत के अनुरूप खाद उपलब्ध नहीं हो रही है।

सोनहत की समितियां खाली–डीएपी,इफको, यूरिया सभी स्टॉक आउट-डीएपी संकट का सबसे गंभीर असर सोनहत ब्लॉक में नजर आया, रिपोर्ट के अनुसार एक भी बोरी डीएपी स्टॉक में नहीं बची, सोनहत,रजौली और रामगढ़ समितियों में इफको और यूरिया भी उपलब्ध नहीं, किसान गेहूँ, चना, तिवरा, मसूर, सरसों जैसी रबी फसलों की बुवाई के लिए खाद को लेकर परेशान हैं, रुद्र साहू ने प्रशासन से तत्काल खाद उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि ÷अगर अभी खाद नहीं मिला, तो पूरी रबी फसल प्रभावित हो जाएगी।

किसानों की आवाज...खाद नहीं–तो फसल नहींज किसके पास जाएँ? स्थानीय किसानों ने बताया कि खाद की तलाश में वे कई समितियों का चक्कर लगा चुके हैं, गेहूं की बुवाई का समय निकल रहा है,दलहन,तिलहन फसलों के लिए डीएपी अत्यंत आवश्यक है, जाएँ भी तो कहाँ जाएँ? यह किसानों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है।

घटती घटना

आवश्यकता है

दैनिक समाचार पत्र में कार्य करने हेतु निम्न पदों के लिए योग्य कर्मठ,जुझारू,महिला/पुरूष की आवश्यकता है।

स.क्र.	पद	संख्या	वेतन
01	सह संपादक	1 पद	15,000
02	समाचार संपादक	1 पद	15,000
03	प्रबंध संपादक	1 पद	15,000
04	विज्ञापन प्रभारी	2 पद	10,000 से 13,000
05	ब्यूरो चीफ	1 पद	10,000 से 13,000
06	संवाददाता	2 पद	8000 से 12,000

नोटः- आवेदक फोन पर संपर्क ना करें। स्वयं बायोडाटा के के साथ कार्यालय में संपर्क करें।

पता :- कार्यालय दैनिक समाचार पत्र घटती-घटना शनि मंदिर के पास,नमनाकला,अम्बिकापुर छत्तीसगढ़, मो0नं0 - 98265-32611

CMYK

न दिलबर,न लॉग लाची,ये है सबसे ज्यादा देखा गया गाना

मिले हैं 5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज

क्या आप यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार सुने गए गाने के बारे में जानते हैं। इसे 5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं और इसने कई और फेमस गानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
टी-सीरीज का भक्ति गीत श्री हनुमान चालीसा इतिहास रच चुका है। यह 5 बिलियन व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय वीडियो बन गया है। जी हां, आपने सही पढ़ा,गुलशन कुमार द्वारा प्रस्तुत इस हनुमान चालीसा ने न सिर्फ भारत में,बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज में अपनी जगह बनाई है। इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और व्यूज़ की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड छू रही है। यह आंकड़ा किसी भी बॉलीवुड, पंजाबी या बड़े सुपरस्टार के गानों से कहीं आगे है।

किसने बनाया यह भक्ति गीत?

श्री हनुमान चालीसा अब तक यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का अकेला वीडियो है। इसके साथ ही यह यूट्यूब के टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज की सूची में शामिल हो गया है, जो किसी भारतीय कंटेंट के लिए बेहद गर्व की बात है। इस श्रद्धापूर्ण प्रस्तुति को हरिहरन ने अपनी आवाज में गाया है और इसका संगीत ललित सेन ने तैयार किया है। टी-सीरीज द्वारा जारी इस वीडियो का निर्देशन शंभू गोपाल ने किया था। यह गीत न सिर्फ एक प्रार्थना है, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए विश्वास और शक्ति का माध्यम बन चुका है।

सोशल मीडिया पर खुशी की लहर

5 बिलियन व्यूज की खबर ने सोशल मीडिया पर उत्साह की लहर दौड़ा दी। एक यूट्यूब यूजर ने लिखा, 5 बिलियन व्यूज पूरा होने के बाद दोबारा सुनने आया हूं। भारत और इस उपलब्धि पर गर्व है। दूसरे यूज़र ने कहा, पूरी तरह डिजर्विंग। ऐसे वीडियो उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। एक अन्य कमेंट में था, भारत और टी-सीरीज के लिए यह कमाल की उपलब्धि है।

भूषण कुमार की प्रतिक्रिया

टी-सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार ने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हनुमान चालीसा लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखती है और मैं भी उनमें शामिल हूं। मेरे पिता गुलशन कुमार ने आध्यात्मिक संगीत को हर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। यह उपलब्धि उनके विजन को सम्मान देने जैसा है। 5 बिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार करना और यूट्यूब के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोज़ की सूची में शामिल होना सिर्फ डिजिटल सफलता नहीं है, यह भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है।

दादा का बॉलीवुड में खूब चला सिक्का

बेटे ने भी कमाया नाम, अब पोता भी बना अजय देवगन की फिल्म का हीरो

अजय देवगन स्टारर फिल्म में बतौर हीरो नजर आने वाले मीजान जाफरी ने भी इस फिल्म के खूब पहचान हासिल की है। अपने पिता जावेद जाफरी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले मीजान भी अब हीरो बन गए हैं और दे दे प्यार दे 2 फिल्म में उन्होंने हीरो बनकर अजय देवगन को भी टक्कर दी है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि मीजान के दादा का भी बॉलीवुड में कभी सिक्का चलता था और 400 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कलाकारी का जलवा दिखा चुके हैं। मीजान के पिता भी बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर हैं। आइये जानते हैं मीजान के करियर के परिवार की पूरी कहानी।

शोले में भी दिखा था दादा का जलवा

मीजान के दादा के नाम था जगदीप और बॉलीवुड की 400 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया था। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार ने उन्हें खूब पहचान दिलाई थी। जगदीप का असल नाम सैयद इश्ताक अहमद जाफरी था और अपने समय के दिग्गज कलाकार रहे हैं। जगदीप ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का खूब सिक्का चलाया और 2020 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जगदीप ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने बेटे जावेद जाफरी को भी बॉलीवुड में पहचान दिलाई। 3 इडियट्स समेत दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लेकर कॉमेडी तक में जान फूंकने वाले जावेद जाफरी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अब जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी ने भी बॉलीवुड में अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है।

अजय देवगन को दी टक्कर

मीजान जाफरी ने साल 2019 में आई फिल्म मलाल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद हंगामा-2 में भी अहम किरदार में नजर आए। हालांकि ये दोनों ही फिल्में उन्हें पहचान नहीं दिला सकीं। इसके बाद यारियां-2 में भी काम किया। लेकिन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दे दे प्यार दे-2 में उन्होंने दमदार किरदार निभाया है। इतना ही नहीं इस फिल्म में मीजान भी अपने किरदार से अजय देवगन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या मीजान आने वाले दिनों अपनी शोहरत का कद पिता और दादा के जितना पहुंचा पाते हैं या नहीं। हालांकि मीजान को फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने काफी पहचान दिला दी है।

आईपीएस अधिकारी पर बनी फिल्म,जिसे देखते ही खरीदार ने मारी ठोकर,उसी ने एक्टर को दिलाया करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड

सच्ची कहानियों पर अक्सर ही फिल्में बनती रहती हैं। हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर भी रेजांग ला की लड़ाई की सच्ची घटना पर ही बनी है, जिसे भारत-चीन युद्ध की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक माना जाता है। सच्ची घटना पर ही बनी एक शानदार फिल्म 2023 में भी रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी और अभिनेता का अभिनय इतना जोरदार था कि रिलीज होते ही ये दर्शकों के दिलों पर छा गई। इस फिल्म के लिए लीड एक्टर को नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को देखने के बाद खरीददारों ने इसे ठोकर मार दी थी। हम बात कर रहे हैं विक्रांत मैसी स्टारर 12वीं फेल की, जिसकी डील पहले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कैंसिल कर दी थी।

विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल

फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने गोवा में हुए 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 12वीं फेल से जुड़ा किस्सा साझा करते हुए बताया था कि विक्रांत मैसी और मेधा शंकर स्टारर फिल्म देखने के बाद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने डील कैंसिल कर दी थी। यही नहीं, विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी और फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने भी उन्हें सलाह दी थी कि वे इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ना करें, क्योंकि उनका मानना था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। उन्होंने कहा- जब मैंने 12वीं फेल बनाई, सभी ने कहा कि ये एक भी दिन नहीं चलेगी।

पत्नी ने विधु विनोद चोपड़ा को दी थी ये सलाह

विधु विनोद चोपड़ा ने इसी दौरान अपनी पत्नी की दी सलाह के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा- मेरी पत्नी को फिल्मों के बारे में काफी जानकारी है। उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज न करूं, विक्रांत की ये फिल्म देखने कोई नहीं जाएगा। मगर मैंने कहा कि ये फिल्म मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है और लोग जरूर देखेंगे और फिर फिल्म टीवी-डिजिटल पर उपलब्ध होने के बाद भी 7 महीने बड़े पर्दे पर टिकी रही।

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कैंसिल कर दी थी डील

विधु विनोद चोपड़ा ने ये भी बताया कि कैसे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म देखने के बाद डील से पीछे हट गया। उन्होंने कहा- 12वीं फेल को लेकर एक ओटीटी कंपनी से मेरी डील पहले ही हो गई थी। मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने फिल्म देखी और कह दिया- हमारे पास फंड नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। मैंने उनसे कहा कि शायद आप फिल्म को समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि सर, अब तो ऐसे लोग हैं ही नहीं। मतलब कि ईमानदारी गायब हो चुकी है। मैंने कहा- मुझे नहीं पता कि ऐसे लोग हैं या नहीं,लेकिन आप एक को कम से कम आप बैठकर यहां देख सकते हैं।

क्या है 12वीं फेल की कहानी

विक्रातं मैसी स्टारर 12वीं फेल की कहानी 2019 में आई अनुराग पाठक की इसी नाम की किताब पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी आईपीएस अफसर मनोज कुमार शर्मा के बारे में है, जो गरीब परिवार से होते हुए और 12वीं में फेल होने के बाद भी आईपीएस अफसर बने थे। फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में हैं और उनके साथ-साथ मेधा शंकर, अनंत जोशी, प्रियांशु चटर्जी और अंशुमान पुष्कर जैसे कलाकार उनके साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे।

एक ही नाम से बनीं दो फिल्में,एक बन गई कल्ट क्लासिक, जीता बेस्ट मूवी का अवॉर्ड,दूसरी निकली सेमी हिट

हिंदी सिनेम के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी भी आईं जो हमेशा के लिए दर्शकों के जेहन में घर कर गईं। जिन्हें बार-बार देखा गया। कहानी-डायलॉग में इतनी गहराई थी कि हर किसी का अर्थ दर्शकों ने अपने-अपने हिसाब से निकाला। दिलचस्प बात यह है कि ये फिल्में जब रिलीज हुईं तब सिनेमाघरों में इन्हें बहुत ज्यादा दर्शक नहीं मिले। समय के साथ-साथ इन फिल्मों के प्रति लोगों में क्रेज बढ़ा । इन फिल्मों की गहराई को लोगों ने समझा. 44 साल पहले ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसने बेस्ट फिल्म फेयर का अवॉर्ड भी जीता था। आज यह फिल्म मास्टरपीस मानी जाती है.बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हिंदी सिनेमा में मास्टरपीस मानी जाती है. 24 जुलाई 1981 को रिलीज हुई कलयुग एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था. शशि कपूर प्रोड्यूसर थे। शशि कपूर ने कॉमर्शियल फिल्मों करके पैसा कमाया और कई आर्ट फिल्में बनाईं। इन्हीं में से एक है कलयुग जिसे बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। यह फिल्म आधुनिक समय की महाभारत कही जाती है। कहानी महाभारत से ली है लेकिन उसका बैकग्राउंड कॉर्पोरेट रखा गया है। कॉर्पोरेट घरानों के बीच की कहानी को महाभारत जैसा दिखाया गया है। एक घराना पांडव जैसा है तो दूसरा कौरवों जैसा है।

खेल-समाचार

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली

- 2030 में अहमदाबाद में होंगे गेम्स
- ओलिंपिक 2036 की दावेदारी मजबूत होगी

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया।
भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते थे।

20 साल बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा

20 साल के बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था।

सीडब्ल्यूजी के अलावा, भारत 1951 और 1982 एशियन गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है। 2003 में हैदराबाद में एफ्रो-एशियन कप का आयोजन भी हुआ था

क्यों खास है सीडब्ल्यूजी की मेजबानी?

कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसी भी देश के लिए सिर्फ खेल आयोजन नहीं, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि, विकास क्षमता, इन्फ्रास्ट्रक्चर और विजन का भी प्रतीक माना जाता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित कुल 9 देश इसकी मेजबानी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 5 बार मेजबानी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है।

ओलिंपिक-2036 की दावेदारी मजबूत होगी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से ओलिंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होगी। भारत 2036 के ओलिंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की से इसका ऐलान किया था। पिछले साल नवंबर में भारत ने ओलिंपिक गेम्स-2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की थी।

इंडिया ने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते

2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत ने कुल 61 मेडल जीते 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। इनमें से 30 मेडल सिर्फ कुश्ती, वेटलिफ्टिंग और एथलेटिक्स से आए थे। महिला क्रिकेट टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता था।

कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास

कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास भी दिलचस्प है। यह एक मल्टी-स्पोर्ट्स अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जिसमें ब्रिटिश शासन वाले देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसमें 54 सदस्य देश हैं। इन गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। 1978 से इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। 2030 के आयोजन में कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 साल पूरे होंगे।

19 वर्षीय सिंडारोव सबसे कम उम्र के चैंपियन बने

पणजी,26 नवम्बर 2025। उज़्बेकिस्तान के टीनएज सेंसेशन जावोखिर सिंडारोव ने चेस के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे बुधवार को गोवा में एक नर्वस करने वाले टाईब्रेक फिनाले में चीन के वेई यी को हराकर चेस वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ऐसे इवेंट में जहां फेवरेट टीमें नॉकआउट स्टेज से पहले एक के बाद एक बाहर हो रही थीं, सिंडारोव ने टूर्नामेंट की शुरुआत सोलहवीं सीड के तौर पर की। उनके लिए टाइटल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने ही देश के नोदिरबेक याकूबबोएव के खिलाफ एक करीबी सेमीफाइनल मैच में, वे टाईब्रेक तक पहुंचने के बाद ही जीते। वेई यी और सिंडारोव दोनों ने चैंपियनशिप राउंड में पहुंचकर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने दूसरे 15% + 10 रैपिड टाईब्रेक में जीत हासिल करने के बाद वेई को रोमांचक मुकाबले में हराकर ट्रॉफी अपने घर ले गए। उनकी जीत शतरंज की दुनिया में एक बड़े बदलाव का भी संकेत है। डी. गुकेश की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत और दिव्या देशमुख की जीत के बाद, सिंडारोव एक साल से भी कम समय में कोई बड़ा वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले तीसरे टीनेजर बन गए हैं।

वनडे में नंबर 1 और टेस्ट में नया कीर्तिमान,रोहित शर्मा ने बढ़ाया रुतबा

दुबई,26 नवम्बर 2025। रोहित शर्मा ओडीआई बैट्समैन में फिर से टॉप रैंक पर आ गए, जबकि ज़िम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा ने अपने करियर में पहली बार टी 20आई ऑल-राउंडर्स रैंकिंग में नंबर 1 जगह हासिल की, जो लेटेस्ट आईसीसी मेन्स टी 20आई प्लेयर रैंकिंग में उनके हालिया मज़बूत फ़ॉर्म को दिखाता है। रज़ा श्रीलंका और मेज़बान पाकिस्तान के साथ चल रही ट्राई-सीरीज़ में अपनी टीम के लिए शानदार फ़ॉर्म में हैं। उनका लेटेस्ट परफ़ॉर्मेंस श्रीलंका के ख़िलाफ़ था, जहाँ उन्होंने तेज़ी से 37 रन बनाए और नौ विकेट से हार में चार किफ़ायती ओवर फेंके। रज़ा का परफ़ॉर्मेंस टी 20आई ऑल-राउंडर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़ने के लिए काफ़ी था, 39 साल के रज़ा अपने 13 साल के इंटरनेशनल करियर में पहली बार टॉप पर पहुँचे।

गोलोम टिंकू ने केआईयूजी 2025 में पुरुष 60 किग्रा में भारत के लिए दिलाया स्वर्ण

बीकानेर,26 नवम्बर 2025। गोलोम टिंकू ने राजस्थान 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुषों की 60 कि.ग्रा. वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नए करियर में एक और उपलब्धि हासिल की। अरुणाचल प्रदेश के 19 साल के इस खिलाड़ी ने पहली बार पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे एडिशन में अपनी पहचान बनाई और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, गोलोम ने कुल 256 कि.ग्रा. उठाकर गोल्ड मेडल जीता।

साउथ अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद भारत डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में पांचवें नंबर पर खिसक गया

नई दिल्ली,26 नवम्बर 2025। बुधवार को यहां बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट 408 रन से हारने के बाद, साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 2-0 से सीरीज़ हारने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की स्टैंडिंग में भारत की रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में शानदार जीत के साथ भारत के यादगार टेस्ट दौरे का अंत किया, 2-0 से क्लीन स्वीप किया और भारतीय ज़मीन पर अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज़ जीती,जो 2000 में ऐतिहासिक जीत के बाद पहली थी। हार का अंतर मेज़बान टीम के लिए चौंकाने वाला था। भारत की 408 रन की हार उनके टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है, इस नतीजे ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 साइकिल में उनके शुरुआती अभियान को भी नुकसान पहुंचाया है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण,1 करोड़ 19 लाख का था ईनाम

बीजापुर,26 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान 'पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन' के तहत बुधवार को 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर एक करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में 12 महिला और 29 पुरुष कैडर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मुख्यधारा में लौटे 41 नक्सली कैडरों में पीएलजीए बटालियन-1 और विभिन्न कंपनियों के 5 सदस्य, एसीएम कैडर के-3, प्लाटून व एरिया कमेटी सदस्य-11,पीएलजीए सदस्य-2, मिलिशिया प्लाटून कमांडर- 4, मिलिशिया डिप्टी कमांडर- 1, मिलिशिया सदस्य-6,जनताना सरकार, डीएकेएमएस,केएएमएस के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य-9 सदस्य शामिल हैं। बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जियें और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। उन्होंने कहा कि माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें। शासन की 'पूना मारगेम' नीति उनके भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने

के लिए हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कैडर : 1. पण्डरू हपका उर्फ मोहन, उम्र 37 वर्ष,साकिन पदेडा रेगडगट्टापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर छग,पदनाम-बटालियन नंबर 1 पीपीसीएम, इनाम- 8 लाख रूपये। 2. बण्डी हपका पति पण्डरू हपका उर्फ मोहन उम्र 35 वर्ष साकिन पदेडा रेगडगट्टापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम-बटालियन नंबर 1 पीपीसीएम, इनाम- 8 लाख रूपये। 3. लक्खू कोरसा (उम्र 37 वर्ष) पदेडा मासापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, कंपनी नंबर 2 पीपीसीएम, इनाम-8 लाख रूपये। 4. बदरू पुनेम (उम्र 35 वर्ष) जाति साकिन पुसनार ध्रुर्वापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम-प्लाटून नंबर 30 पीपीसीएम, इनाम-8 लाख रूपये।5. सुखराम हेमला (उम्र 27 वर्ष) साकिन काकेकोरमा गुबालीपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम- प्लाटून नबर 50 पीपीसीएम, इनाम-8.लाख रूपये। 6. मंजूला हेमला उर्फ शांति (उम्र 25 वर्ष) साकिन काकेकोरमा गुबालीपारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर,पदनाम-प्लाटून नंबर 50 पार्टी सदस्या इनाम 8 लाख रूपये। 7. मंगली माडवी उर्फ शांति उर्फ मंगलो (उम्र 29 वर्ष) साकिन कोतरापाल लक्खापारा थाना जांगला जिला बीजापुर, पदनाम- कंपनी नंबर 2 पार्टी सदस्या, इनाम-8 लाख रूपये। 8.जयराम कडियम (उम्र 28 वर्ष) साकिन सावनार मुकापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम-कंपनी नंबर 2 पार्टी सदस्य,इनाम - 8 लाख रूपये। 9.पाण्डो मडकम उर्फ चांदनी (उम्र 35 वर्ष) साकिन कोतरापाल लक्खापारा थाना जांगला जिला बीजापुर, पदनाम- कंपनी नंबर 5 पार्टी सदस्या, इनाम-8 लाख रूपये।

10. माटा कडियम उर्फ मंगल(उम्र 28 वर्ष) साकिन मेटापाल तेलगापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर,पदनमा भैरमगढ एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम),इनाम -5 लाख रूपये।

11. जमली कडियम पति माटा कडियम उर्फ मंगल उम्र 26 वर्ष साकिन मेटापाल तेलगापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर छ0ग पदनाम- भैरमगढ एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम),इनाम-5 लाख रूपये।

12. जोगी मडकम उर्फ मालती (उम्र 28 वर्ष) साकिन सिंघनपल्ली स्कूलपारा थाना उसूर जिला बीजापुर, पदनाम-धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ (डीजीएन) डीविजन सदस्य (एसीएम), पदनाम-5 लाख रूपये।

13. छोटू कारम (उम्र 25 वर्ष) साकिन हिरोली गायतापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम-तेलंगाना स्टेट कमेट पार्टी सदस्य, इनाम -2लाख रूपये।

14. अनिल मड़कम उर्फ मूडा (उम्र 20 वर्ष) साकिन पेद्दापाल नयापारा थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम-पश्चिम बस्तर डीविजन सप्लाई टीम पार्टी सदस्य, इनाम 2 लाख रूपये।

छत्तीसगढ़ में ट्रक-स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 की मौत

आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार,मृतकों में 2 सेना के जवान

जांजगीर-चांपा,26 नवम्बर 2025। जिले में बीती रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। थाना जांजगीर क्षेत्र के ग्राम सुकली चौक हाइवे रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देर रात लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ। अचानक हुई इस दुर्घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक,ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि टक्कर लगते ही स्कॉर्पियो कई मीटर तक घिसटती चली गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहन में सवार सभी पाँच लोगों की सांसें घटनास्थल पर ही थम गईं। हादसे की सूचना मिलते ही जांजगीर पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस टीम ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को पास के अस्पताल भेजा। मृतकों के शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रातभर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर फरार आरोपी ट्रक

चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अजीत कुमार पिता हरिंदर राय, उम्र 23 वर्ष, निवासी मूडा, थाना गोरखा, जिला छपरा (बिहार) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि रात में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया और यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। स्थानीय लोगों में इस दुर्घटना को लेकर बेहद गुस्सा और दुख देखने को मिला। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। वाहन को तकनीकी जांच हेतु जब्त किया गया है और हाईवे पर दुर्घटना के कारणों को लेकर भी व्यापक समीक्षा की जा रही है।

आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने पेश किया छठवां पूरक चालान

रायपुर,26 नवम्बर 2025। रायपुर में आबकारी विभाग से जुड़ा बड़ा घोटाला मामले में ईस्टर्न विंग (ईओडब्ल्यू) ने छठवां पूरक चालान विशेष कोर्ट में पेश किया। इस चालान में कुल 6 आरोपियों को नामजद किया गया है। आरोपियों में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास,अतुल सिंह,मुकेश मनचंदा,नितेश पुरोहित,यश पुरोहित और दीपेंद्र चावड़ा शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने चालान में 7 हजार पन्नों के सबूत और दस्तावेज अदालत को सौंपे हैं। यह चालान इस मामले में अब तक पेश किए गए पूरक चालानों में छठा है,जो जांच में सामने आए नए तथ्य और सबूतों को अदालत के समक्ष रखता है। विशेष कोर्ट में चालान पेश करने के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने मामले की संपूर्ण जानकारी अदालत को दी। आबकारी घोटाला मामले में आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और अन्य आरोपियों ने वर्ष 2019-2022 के दौरान शराब और अन्य आबकारी वस्तुओं से जुड़े लेन-देन में भारी अनियमितताएं कीं। जांच में यह सामने आया कि आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी और निजी व्यक्ति मिलकर सरकारी कोष का नुकसान करने वाले घोटाले में शामिल थे।ईओडब्ल्यू की टीम ने कहा कि चालान में आरोपियों की भूमिका स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है और प्रत्येक आरोप के साथ साक्ष्य भी जोड़े गए हैं। इससे पहले,इस मामले में कई चरणों में पूरक चालान पेश किए जा चुके हैं। पहले के चालानों में भी अधिकारियों और अन्य आरोपियों की कथित भूमिका का विवरण दिया गया था। विशेष कोर्ट में चालान पेश होने के बाद अब अदालत इस मामले की सुनवाई के लिए आगे की प्रक्रिया तय करेगी। अदालत इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें न्यायालय में पेश करने के आदेश दे सकती है। आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच के दौरान कई दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन कर आबकारी विभाग से संबंधित लेन-देन में अनियमितताएं कीं।

एनएमडीसी प्लांट का कर्मचारी कन्वेयर बेल्ट में फंसा,मौत

दंतेवाड़ा,26 नवम्बर 2025। एनएमडीसी के बचेली प्लांट में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां स्क्रीनिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। इस हादसे से प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार,हादसा डिपॉजिट नंबर-05 में तब हुआ, जब कर्मचारी शिव कुमार ड्यूटी पर काम कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर परिजन और कर्मचारी यूनियन ने एनएमडीसी प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बचेली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,कई अधिकारियों के तबादले

रायपुर,26 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा के 16 अधिकारियों की तबादला किया गया है। सचिवालय सेवा के 16 अनुभाग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अलग पदों पर पदस्थ किया गया है। इस सूची के अनुसार,जेल विभाग में पोस्टेड अनुभाग अधिकारी अभिलाषा दास को सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9) में भेजा गया है।

संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,26 नवम्बर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान पर आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत सदैव संविधान में आस्था रखते हुए आगे बढ़ रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के

साथ अपनी बात रखने का अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद जैसे पदों पर आम नागरिकों का पहुँचना संविधान की ही उदार, समावेशी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने संविधान निर्मात्री सभा में देश के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संविधान निर्माण अमूल्य योगदान दिया को स्मरण किया। उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ से भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठजनों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक भागीदारी आज भी गर्व का विषय है और इन महान जनप्रतिनिधियों की विचारशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य और राष्ट्रनिर्माण की दृष्टि सदैव प्रेरणा देती रहेगी। इस अवसर पर विधायक राजेश मूणत,विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सविलयन से पहले शिक्षा विभाग में नहीं थे शिक्षाकर्मी

हाईकोर्ट ने कहा...इसलिए क्रमोन्न्ति के लिए पात्र नहीं,1188 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज

रायपुर,26 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 साल सेवा अवधि के बाद शिक्षकों की क्रमोन्नति की मांग वाली 1188 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में कहा है कि संविलयन से पहले शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन नहीं थे। इसलिए उन्हें क्रमोन्नति पाने की पात्रता नहीं है।

कोर्ट परिसर सुरक्षा उपकरण : दरअसल, पंचायत विभाग में नियुक्त शिक्षाकर्मी ग्रेड-3, 2 और 1 का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। इसके बाद उन्हें सहायक शिक्षक (एलबी), शिक्षक (एलबी) और व्याख्याता (एलबी) पदनाम दिया गया। लेकिन, इन शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया, जिस पर प्रदेश भर के 1188 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई। इसमें कहा गया कि वे 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद क्रमोन्नति के हकदार हैं। लेकिन विभाग ने

2017 का वह आदेश लागू नहीं किया, जिसमें 10 साल बाद वेतनवृद्धि (क्रमोन्नति) देने की बात कही गई थी। शिक्षकों ने सोना साहू के मामले में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की थी।

संविलियन से पहले शासकीय सेवक नहीं थे : इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षाकर्मी ग्रेड-3/ सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत नियुक्त हुए थे और उनकी सेवा व नियंत्रण जनपद पंचायत के अधीन था। ऐसे में उन्हें संविलियन से पहले राज्य शासन का नियमित सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता। वे क्रमोन्नति देने के लिए 10 मार्च 2017 को जारी सर्कुलर के आवश्यक मानदंड पूरी नहीं करते, क्योंकि उनकी सेवा अवधि की गणना केवल 1 जुलाई 2018 यानी संविलियन की तारीख से ही की जा सकती है।

इसी के चलते वे 10 वर्ष की अनिवार्य योग्यता पूरी ही नहीं करते। हाईकोर्ट ने शासन के न तर्कों को सही माना है। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सोना साहू मामले का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सोना साहू केस के तथ्य पूरी तरह अलग है, इसलिए समानता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

रायपुर के कारोबारी ने तोमर बंधुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई

रायपुर,26 नवम्बर 2025। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और मारपीट के मामलों में हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी और रोहित तोमर के खिलाफ मंगलवार को देवेंद्र नगर थाने में ब्लैकमेलिंग और ठगी का एक और केस दर्ज किया गया। 5 माह में दोनों भाइयों पर दर्ज यह आठवां केस है। शंकर नगर निवासी संजय चांडक ने शिकायत में बताया कि 8 अगस्त 2021 को वीरेंद्र तोमर परिवार के साथ दुकान में आया था। वह अपने नए घर के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर सहित अन्य सामान ले गया. वह दोबारा भी आया और सामान खरीदा। कुल 10.50 लाख रुपए का सामान लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। एक साल तक फोन करने पर गुमराह करता रहा। बाद में धमकाने लगा. इससे डरकर चांडक शांत हो गया. अब वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है. तोमर ब्रदर्स के खिलाफ इस साल पांच माह में मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के 8 केस दर्ज हुए हैं। तेलीबांधा में

रोहित के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है। कारोबारी नरेश सचदेवा ने 2.5 लाख कर्ज लेकर 20 लाख लौटाए. गोपाल कुमार ने 2 लाख लेकर 28 लाख लौटाए। हरीश कछवाहा ने 3.5 लाख लेकर 50 लाख लौटाए. जयदीप बैनर्जी ने 16 लाख लेकर 52 लाख चुका दिए हैं।

विदेशी शराब लेकर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी,शराब लूटने की मची होड़

पामगढ़/शिवरीनारायण,26 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले के पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में विदेशी शराब लेकर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की जानकारी मिलते शराब लूटने ग्रामीणों में होड़ मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और बाकी बची शराब की शिफ्टिंग कराई। जानकारी के अनुसार बिलासपुर से जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जा रही विदेशी शराब से भरी गाड़ी बिलासपुर शिवरीनारायण मुख्य मार्ग में जुनेजा पेट्रोल पंप पामगढ़ से कुछ दूर पहले अचानक अनियंत्रित होकर नाला से नीचे पलट गई। गाड़ी में गोवा, बियर ब्रांड की 495 कार्टून शराब थी। जिसमें से लगभग 25 से 35 से ज्यादा कार्टून की शराब की बोतल टूट गईं है। सुबह होते ही आसपास के कई लोग शराब लूटने टूट पड़े। कई लोग शराब लूटकर फरार भी हो गए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची तो लोग मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पामगढ़ पुलिस घटनास्थल पहुंच गई थी। पामगढ़ थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा अपने टीम सहित मौजूद रहे। साथ ही आबकारी विभाग के सुपरवाइजर सहित विभाग की कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद शराब की पेटी को सुरक्षित माजदा में शिफ्ट की गई।

CGPSC 2025 : 238 पदों पर भर्ती....29 सीएमओ,14 डिप्टी कलेक्टर और राज्य पुलिस के 28 पद,प्रीलिम्स 22 फरवरी को,पुराने पैटर्न पर एग्जाम

रायपुर,26 नवम्बर 2025। सीजीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां होंगी। सबसे ज्यादा पद मुख्य नगर पालिक अधिकारी के लिए हैं,कुल 29 पद। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा में 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पद हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच किए जा सकते हैं। पिछले साल की तरह, इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार होगी। बता दें कि पिछली बार कुल 246 पदों के लिए भर्ती की गई थी।

नियमों में बदलाव नहीं, पुराने पैटर्न से होगा एग्जाम : सीजीपीएससी 2025 को लेकर यह संभावना थी कि इस बार नियमों में संशोधन होगा,लेकिन इस बार भी कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। पिछली बार की तरह ही प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। सिलेबस भी

4 साल बाद फिर सीएमओ की पोस्ट

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ख और ग वर्ग की भर्ती के लिए पहले एक परीक्षा होती थी, लेकिन 2019 में नियमों में बदलाव किया गया। इसमें यह कहा गया कि इन पदों पर भर्ती राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम होगी। CGPSC 2020 की वैकेंसी में इन पदों को भी शामिल किया गया। तब कुल 6 पदों पर भर्ती हुई थी। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीखें 16, 17, 18 और 19 मई 2026 निर्धारित की गई हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025, रात 11:59 बजे है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)